सुविचार

खुद पर अडिग विश्वास रखो, मेहनत को तपस्या बना लो, डर को मन से मिटा दो, बड़ी सोच ही महान जीत का रहस्य है।

–गौतम बुद्ध

Daily

THE PHOTON NEWS

सच के हक में...

द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi • Wednesday, 06 May 2026 • Year : 05 • Issue : 110 • Ranchi Edition • Page : 12 • Price : ₹3 • www.thephotonnews.com E-Paper : epaper.thephotonnews.com

12

Jacqueline Fernandez To Return To Cannes Film Festival 2026...

SHARE

संसेक्स	:	77,017.79
निफ्टी	:	24,032.80

SARAFA

सोना	:	13,865
चांदी	:	265.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

कोलकाता पुलिस के डीसीपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस

KOLKATA : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह लुकआउट नोटिस बिस्वास द्वारा ईडी की ओर से जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के बाद जारी किया गया है। अधिकारी ने बताया कि बिस्वास द्वारा भारत छोड़ने के किसी भी संभावित प्रयास को रोकने के लिए नोटिस को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य जगहों पर वितरित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी

NEW DELHI : मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में 33 न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश हैं। इस संख्या को चार और बढ़ाने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। उन्होने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। इसमें 3936 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। इनमें गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले इकाई और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई शामिल है।

अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं : हेमंत सोरेन

- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधि–व्यवस्था को लेकर की बैठक
- आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दिया निर्देश
- संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए हर स्तर पर उठाए जाएं कड़े कदम

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बेहतर विधि-व्यवस्था सुदृढ़ बनाने को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय भूमिका में रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा। बैठक में उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को राज्य के भीतर कानून-व्यवस्था की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने तथा आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को चिह्नित कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। मुख्यमंत्री ने जिलों में पदस्थापित एसपी, डीएसपी एवं प्रभारी अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों में निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर आम जनता के साथ निरंतर संवाद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा सहित सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी तथा सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

लापता बच्चों और महिलाओं के मामलों पर हो त्वरित कार्रवाई

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में लापता बच्चों और महिलाओं से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए लापता बच्चों और महिलाओं की सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आम जनों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।

नशीले पदार्थों के कारोबार पर लें हार्ड एक्शन

मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी सप्लाई चेन को तोड़ा जाए। साथ ही उन स्थानों को चिह्नित किया जाए, जहां नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री होती है, विशेषकर स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास कड़ी निगरानी रखी जाए।

कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा–

नहीं दूंगी इस्तीफा, चुनाव परिणाम जनादेश नहीं, बल्कि बड़ी साजिश

KOLKATA @ PTI : मंगलवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम जनादेश नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश है। साथ ही उन्होंने सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने और विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प लिया। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उसकी लड़ाई देश के निर्वाचन आयोग से थी, जिसने भाजपा के लिए काम किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के एक दिन बाद बनर्जी ने कहा, मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी हार जनता के जनादेश से नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत हुई है। मैं हारी नहीं हूं, हराया गया है, मैं लोकभवन नहीं जाऊंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने कहा, मुझे इस्तीफा क्यों देना चाहिए, हम हारे नहीं हैं। मतों की लूट हुई है। इस्तीफे का सवाल ही कहां उठता है।

मैं हारी नहीं हूं, हराया गया है, नहीं जाऊंगी लोकभवन

- मतों की लूट हुई है, इस्तीफे का सवाल ही कहां उठता 100 सीटों पर लूटा गया जनादेश
- किसी पार्टी से नहीं थी लड़ाई देश के निर्वाचन आयोग ने भाजपा के लिए किया काम
- सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ने और 'इंडिया' गठबंधन को मजबूत करने का लिया संकल्प

जानबूझकर धीमी कर दी गई थी मतगणना

निवर्तमान मुख्यमंत्री बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दावा किया कि लगभग 100 सीटों पर जनादेश को लूट लिया गया और उनकी पार्टी का मनोबल गिराने के लिए जानबूझकर मतगणना धीमी की गई। उन्होंने कहा, हम भाजपा से नहीं लड़ रहे थे; हम निर्वाचन आयोग से लड़ रहे थे जो भाजपा के लिए काम कर रहा था। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त खलनायक बन गए हैं। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां और अधिकारी मिलीभगत से काम कर रहे थे और दावा किया कि छापेमारी, तबादले और पक्षपात ने हालात ऐसे बना दिए कि मुकाबला निष्पक्ष ना रहे और संस्थानों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनसे फोन पर बात की थी।

बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण नौ को

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं और शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने जानकारी दी है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण आगामी नौ मई को किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष भट्टाचार्य ने बताया कि नौ मई का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस दिन कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है।

विधायक दल के नेता बने विजय

CHENNAI : मंगलवार को चेन्नई के पनैयूर स्थित टीवीके मुख्यालय में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सरकार गठन को लेकर मंथन किया गया। बैठक के दौरान सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से विजय को तमिलगा वेत्रि कझगम (टीवीके) के विधानसभा दल का नेता चुन लिया है।

शाह बंगाल व नड्डा असम का बने केंद्रीय पर्यवेक्षक

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गृहमंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को असम में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक दलों के नेताओं के चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने मंगलवार को बताया कि भाजपा संसदीय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गृहमंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अरुण सिंह ने बताया कि भाजपा संसदीय बोर्ड ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चयन के लिए पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

लातेहार में टीएसपीसी के उग्रवादी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बताए कई राज

जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी • फोटोन न्यूज

- 15 सालों से संगठन से जुड़ा हुआ है उप–क्षेत्रीय कमांडर विरम राम उर्फ अरविंद
- एक पिस्तौल, सात कारतूस, एक मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद
- राज्य के विभिन्न जिलों में विरम के खिलाफ लंबित हैं कम से कम 16 आपराधिक मामले

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को लातेहार जिले की पुलिस को उग्रवादियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के एक उप-क्षेत्रीय कमांडर विरम राम उर्फ अरविंद को गिरफ्तार किया है। उसने पुलिस को कई राज बताए हैं। उसके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 42 वर्षीय यह व्यक्ति पिछले 15 वर्ष से टीएसपीसी से जुड़ा हुआ है। राज्य के विभिन्न जिलों में उसके खिलाफ कम से कम 16 आपराधिक मामले लंबित हैं। रांची ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी ने बताया, रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपी को लातेहार जिले के चंदवा थाना अंतर्गत उसके घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल, सात कारतूस, एक मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान उसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए हैं। गोस्वामी ने बताया कि उनमें से कई को या तो गिरफ्तार किया जा चुका है या सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पुलिस इन लोगों को समर्थन देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। सोमवार को बुरमू पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि बुढ़मू थाना क्षेत्र के ईंट भट्ठों पर फायरिंग करने वाला कुख्यात उग्रवादी विरम राम उर्फ अरविंद को चंदवा के धोबी टोला में देखा गया है। एक विशेष टीम गठित कर पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से धोबी टोला स्थित उसके मकान की घेराबंदी की।

गुमला से लापता बच्ची के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा–

बच्ची का पता नहीं चल पाना पुलिस की लापरवाही

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला से साल 2018 में लापता छह वर्षीय बच्ची के मामले में सुनवाई के दौरान गुमला पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि करीब सात साल बीत जाने के बाद भी बच्ची का पता नहीं चल पाना पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। न्यायालय ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस को एक और साल चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आना गुमला पुलिस की जांच में गंभीर कमी को उजागर करता है। अदालत ने यह संकेत भी दिया कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जा सकता है। यह मामला सितंबर 2018 से लापता बच्ची की मां चंद्रमुनि उराइन द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश पर गुमला के पुलिस अधीक्षक (एसपी), विशेष जांच दल (एसआईटी) के प्रमुख और जांच अधिकारी उपस्थित हुए। झारखंड सरकार की ओर से बताया गया कि नई गठित एसआईटी की तीन टीमें बच्ची की तलाश में मुंबई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तक गई हैं।

गिरिडीह में पिकअप वैन ने 3 लोगों को रौंदा, दो की मौके पर ही हुई मौत

PHOTON NEWS GIRIDIH : मंगलवार को जिले के बिरनी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर जान चली गई गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा सरिया-राजधनवार मुख्य मार्ग पर माखमरगो पंचायत भवन के सामने हुआ। मृतकों की पहचान 70 वर्षीय बासदेव साव 65 वर्षीय लखिया देवी के रूप में हुई है। इस हादसे में 65 वर्षीय धनपत साव गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया कि तीनों बिरनी थाना क्षेत्र के जितकुंडी गांव के निवासी थे। वे रोज की तरह माखमरगो इलाके में मजदूरी करने के लिए पैदल जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी।

यूएई के फुजैराह में ईरान के ड्रोन हमले की प्रधानमंत्री ने की निंदा

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज से सुरक्षित आवागमन होना बहुत जरूरी : पीएम मोदी

AGENCY NEW DELHI : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के फुजैराह पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र पर ईरान के ड्रोन हमले की निंदा की है। हमले से आग लग गई और वहां काम कर रहे तीन भारतीय नागरिक घायल हो गए। उन्होंने नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने को अस्वीकार्य बताते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें तीन भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ पूरी तरह एकजुट है और संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है।

बिग इंपैक्ट लगभग 10 वर्षों में स्वीकृत किए गए 52.37 करोड़ से अधिक ऋण

अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मुद्रा योजना ने निभाई अहम भूमिका

PHOTON NEWS, RESEARCH DESK : साल 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरूआत की थी। इसके तहत चार श्रेणियां में 10 हजार से 20 लाख रुपये तक का लोन देने की व्यवस्था की गई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों में यदि किसी क्षेत्र की सबसे अधिक भूमिका है, तो वह है सूक्ष्म और लघु उद्यमों का विशाल नेटवर्क। यह नेटवर्क जितना मजबूत होता है, रोजगार के उतने ज्यादा अवसर भी पैदा होते हैं। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए इस योजना के फलक को व्यापक बनाया गया। विभाग की ओर से पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां को ध्यान में रखकर जारी की गई हालिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस योजना ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि इस योजना के तहत अब तक 52.37 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। लोन के माध्यम से 33.65 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। बीते एक दशक में देश के करोड़ों लोगों को वित्तीय सहारा देने के साथ आर्थिक संरचना को भीतर से सशक्त करने के उपाय का हर स्तर पर प्रयास किया गया। यह सही है कि नोटबंदी के बाद इस योजना पर कुछ नकारात्मक असर पड़ा था, लेकिन बाद में धीरे–धीरे संभाल लिया गया।

लोन के माध्यम से 33.65 लाख करोड़ रुपये की राशि का किया जा चुका है वितरण

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों की मदद के लिए 2015 में शुरू हुई थी योजना
- युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से स्कीम को मिला व्यापक फलक
- आर्थिक संरचना को भीतर से सशक्त बनाने के लिए हर स्तर पर उचित उपाय का हुआ प्रयास
- विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थानों ने की है योजना की सराहना

- पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं से छोटे उद्यमियों को किया गया मुक्त

ऋण उपलब्धता को मिली नई दिशा

रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि किस तरह देश में लंबे समय तक छोटे उद्यमियों के सामने बिना गारंटी के सुलभ ऋण की उपलब्धता संभव नहीं थी। पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था में जटिल प्रक्रियाओं और गारंटी की शर्तों की वजह से छोटे कारोबारी वित्तीय सहायता से वंचित रह जाते थे। ऐसे में मुद्रा योजना ने इस बाधा को तोड़ते हुए बैंक, एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराकर उद्यमिता को नई दिशा दी। यही कारण है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाओं ने इस योजना की सराहना की है।

महिलाओं की भागीदारी

रिपोर्ट में विस्तार से तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट किया गया है कि इस योजना की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। टोटल स्वीकृत लोन में लगभग 70 प्रतिशत महिला उद्यमियों की भागीदारी रही। इससे यह पता चलता है कि हैयोजना सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बनी है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में महिलाएं अब स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं।

हैदराबाद-चंडीगढ़ फ्लाइट में यात्री के पावर बैंक में विस्फोट

KOLKATA : मंगलवार को इंडिगो की एक फ्लाइट हैदराबाद से चंडीगढ़ पहुंची, जिसमें करीब 200 पैसेंजर और क्रू मेंबर थे। लैंडिंग के बाद खड़े होने पर एक पैसेंजर ने देखा कि उसके पावर बैंक में आग लग गई है। क्रू को तुरंत बताया गया और उन्होंने पैसेंजर को इमरजेंसी एग्जिट से जल्दी से बाहर निकाला। आग को फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया गया। इस घटना की वजह से प्लेन का केबिन धुएं से भर गया। इंडिगो ने घटना की पुष्टि की। बताया कि एक पैसेंजर के पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आग लग गई। सुरक्षा कारणों से तुरंत सभी को बाहर निकाला। संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।

पलामू, चाईबासा व दुमका को पहली बार मिले कोषागार पदाधिकारी

- वेतन मामले में फर्जी निकासी के बाद ट्रेजरी सिस्टम की मजबूती के लिए बड़ा फैसला
- वित्त विभाग ने संकल्प जारी कर सभी 47 पदों का किया पुनर्गठन
- भुगतान की निगरानी व नियंत्रण को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया कदम

PHOTON NEWS RANCHI : हेमंत सरकार ने ट्रेजरी सिस्टम को अधिक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला किया है। हजारीबाग कोषागार में लगातार बढ़ते काम के दबाव को देखते हुए सरकार ने कोषागार पदाधिकारी का एक नया पद सृजित किया है, ताकि वहां कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी। दुमका, चाईबासा और पलामू जैसे महत्वपूर्ण जिलों में पहली बार कोषागार पदाधिकारी के पद सृजित किए गए हैं। अब तक इन जिलों में केवल वरीय और सहायक कोषागार पदाधिकारी के पद ही थे, लेकिन शीर्ष स्तर के पद की कमी के कारण कार्यों के संचालन में दिक्कतें आती थीं। इस कमी को दूर करते हुए वरीय कोषागार पदाधिकारी के पदों को प्रत्यर्पित कर नए पद स्थापित किए गए हैं। हाल में वेतन मद में फर्जी निकासी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने कोषागार व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में वित्त विभाग ने संकल्प जारी किया है।

BRIEF NEWS

रामगढ़ में पुलिया टूटी, आवागमन हुआ बाधित

RAMGARH : रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के कोठार में वार्ड संख्या-29 स्थित एक पुलिया सोमवार को ध्वस्त हो गई, जिससे एनएच-23 से जेल रोड और वार्ड संख्या-32 की ओर जाने वाला मार्ग बाधित हो गया। पुलिया गिरने के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना इस मार्ग का उपयोग करने वाले लोग और वाहनों को अब लंबा रास्ता करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पुलिया का निर्माण 2013-14 में किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव था, जिसके कारण पुलिया समय से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब पूरी तरह ध्वस्त हो गई। लोगों का ये भी कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुलिया को दुरुस्त कर लिया जाएगा।

आयुक्त ने किया चंदवा के अंचल कार्यालय का निरीक्षण

LATEHAR : प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय ने मंगलवार को लातेहार जिले के चंदवा स्थित अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कार्यालय में संधारित विभिन्न दस्तावेजों, अभिलेखों एवं पंजियों का अवलोकन किया तथा कार्यों में पारदर्शिता, तत्परता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आयुक्त ने विशेष रूप से लंबित प्रमाणपत्रों, दाखिल-खारिज मामलों एवं अन्य राजस्व संबंधी आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करते हुए आम जनता को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को अनावश्यक विलंब का सामना नहीं करना पड़े, इसका ख्याल रखें। राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण में शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और तय समयसीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस एवं प्रभावी पहल सुनिश्चित की जाए।

रामगढ़ नप में भ्रष्टाचार को लेकर डीसी से शिकायत

RAMGARH : नगर परिषद कार्यालय भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। यह मुद्दा एक बार फिर रामगढ़ डीसी के समक्ष उठाया गया। मंगलवार को डीसी ऋतुराज की ओर से आयोजित जनता दरबार में शिकायत करने कई लोग पहुंचे। समाजसेवी रवि कुमार ने डीसी को बताया कि नगर परिषद की कार्यप्रणाली काफी भ्रष्ट है। सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल पदमुक्त करने और उनके कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। प्रधानमंत्री आवास योजना में नियमों की धज्जियां उड़ाने, बिना किसी विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के अवैध नियुक्तियां की गई हैं।

असम जा रहा था परिवार, सड़क हादसे में एक की मौत, कई घायल

डिवाइडर से टकराकर उछल गई थी कार, उड़े परखच्चे

PHOTON NEWS GODDA : गोड्डा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें रांची के एक परिवार की स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा अमडीहा ओवरब्रिज पर मंगलवार को सुबह करीब 6 बजे हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी करीब 35 फीट दूर जाकर दूसरे डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। जानकारी के अनुसार परिवार रांची से गुवाहाटी जा रहा था, जहां से उन्हें असम के सिलचर में एक शादी समारोह में शामिल होना था। हादसे में सारा तिवारी (17) की कार में छह लोग सवार थे, जिसमें रूपा चौधरी और उसकी बेटी चेरी तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में चल रहा है। देव तिवारी और ब्यूटी सिंह को बेहतर इलाज के लिए देवघर एम्स रेफर किया गया है, जबकि सोनू सिंह को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। पथरगामा थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त कार व जुटे लोग

मोबाइल देखते-देखते रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया छात्र, ट्रेन से कटकर मौत

DUMKA : दुमका में मंगलवार को दसवीं कक्षा के एक छात्र की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जाता है कि वह मोबाइल फोन देखते हुए रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी ट्रेन आ गई। लोगों ने बताया कि प्रभु राय मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। वह दुमका-रामपुरहाट रेलखंड पर स्थित अंबाजोड़ा-शिकारीपाड़ा स्टेशन से आगे की ओर जा रहा था। वह मोबाइल में इतना खोया हुआ था कि चलते-चलते रेल पटरी पर पहुंच गया और इसी बीच ट्रेन आ गई। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। 15 वर्षीय छात्र शिकारीपाड़ा थाना के मुख्य बाजार में होटल संचालक शिवपूजन राय का बेटा था। घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी उसके पिता शिवपूजन राय को दी। वे लोग घटना स्थल पहुंचे। पिता शिवपूजन राय ने बताया कि प्रभु हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए बाजार की ओर जाता था, लेकिन आज मोबाइल चलाते हुए पता नहीं कैसे रेल लाइन की तरफ चला गया। घटना के बाद रेल पुलिस और शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

घटनास्थल पर जुटे परिजन व अन्य

मेयर व नगर आयुक्त में बढ़ी तल्खी आरोप-प्रत्यारोप जारी

HAZARIBAG : हजारीबाग नगर निगम के नगर आयुक्त ओमप्रकाश गुप्ता और महापौर अरविंद कुमार राणा के बीच तल्खी बढ़ गई है। महापौर ने नगर आयुक्त पर जनप्रतिनिधियों के अधिकार की अनदेखी का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, नगर आयुक्त का कहना है कि सभी काम नियम के मुताबिक हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। दोनों की तल्खी से आम नागरिक परेशान हैं। उनका कहना है कि इस तरह से खटास बनी रहेगी, तो जनता का काम कैसे होगा। अरविंद राणा का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है। काम करने से रोका जा रहा है। झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 में महापौर को निगम का प्रथम नागरिक और लोकसेवक माना गया है। हजारीबाग में इन प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है। 25 अप्रैल को हुई बैठक के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। बैठक के बीच में ही आयुक्त एएमसी को जिम्मेदारी देकर निकल गए, जो पूरी तरह से अनुचित है। महापौर ने कहा कि उनके ऑफिस के पियून को हटा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति उनके दफ्तर में आता है तो पानी देने के लिए भी कोई नहीं है। यही नहीं, नगर आयुक्त जो बैठक करते हैं, इसकी जानकारी भी महापौर को नहीं दी जाती है। आयुक्त ने मीडिया में बयान देने के पहले भी इजाजत मांगने की बात कही है, जो यह स्पष्ट करता है कि वह अपना एकाधिकार चलाना चाहते हैं।

प्रिंस खान का करीबी सैफी उर्फ मेजर फिर पुलिस की रिमांड पर

AGENCY DHANBAD : पुलिस वासेपुर गैंग के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगातार जुटी हुई है। भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के खास गुर्गे सैफी अब्बास नकवी उर्फ मेजर को एक बार फिर मंगलवार को एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होने की बात सामने आ रही है। धनबाद थाना में सैफी अब्बास नकवी से पूछताछ जारी है। खुद एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव सहित कई डीएसपी थाना पहुंचकर पूछताछ में शामिल हैं। सूत्रों की मानें तो आज ही सैफी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। इससे पहले भी धनबाद पुलिस सैफी को दो बार, तीन-तीन दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। पश्चिम बंगाल से लाए जाने के बाद पुलिस ने उससे गैंग के पूरे नेटवर्क, फंडिंग और ऑपरेशन के तरीकों को लेकर कई अहम जानकारी हासिल की है। सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान कुछ सफेदपोश लोगों और कुछ तथाकथित यूट्यूब पत्रकारों के नाम भी सामने आए हैं। आरोप है कि ये लोग प्रिंस खान के धमकी भरे वीडियो को वायरल कर शहर में भय का माहौल बनाने और उसके अपराधों को बढ़ावा देने का काम करते थे।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

झारखंड में चांसलर पोर्टल का यूआरएल बदला, नए लिंक से करें आवेदन

JAMSHEDPUR : झारखंड के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में नामांकन और पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के लिए उपयोग होने वाले चांसलर पोर्टल का आधिकारिक वेब पता (यूआरएल) बदल दिया गया है। अब छात्र-छात्राएं पुराने लिंक की जगह नए पोर्टल https://universities.jharkhand.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा https://jharkhanduniversities.nic.in पर उपलब्ध थी। यह बदलाव उच्चतर व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया गया है। सभी विश्वविद्यालयों ने नोटिस जारी कर छात्रों को इसकी जानकारी दे दी है। नोटिस में कहा गया है कि पोर्टल के अपडेटेड वर्जन को सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू करने और छात्रों को आसान व सुलभ पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। साथ ही, इस बदलाव की सूचना सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को भी दे दी गई है, ताकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

नारी शक्ति वंदन पर दिखा भाजपा का दोहरा चरित्र : दयामनी बारला

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नलिनी सिन्हा की अध्यक्षता में बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय (तिलक पुस्तकालय) में मंगलवार को प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि दयामनी बारला ने भाजपा की नीतियों और बयानों पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के मुद्दे पर भाजपा का रवैया पूरी तरह विरोधाभासी है। एक ओर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर महिलाओं को वास्तविक सशक्तीकरण से वंचित रखा जा रहा है। बारला ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा जिस प्रकार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि महिलाओं के साथ अन्याय भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर लागू करने में देरी की जा रही है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है। भाजपा केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित नजर आती है। यदि महिलाओं के हितों के प्रति भाजपा की सच्ची प्रतिबद्धता है, तो 2023 के महिला आरक्षण कानून को तत्काल प्रभाव से लागू क्यों नहीं करती। उन्होंने भाजपा द्वारा प्रस्तावित मशाल जुलूस को महज राजनीतिक प्रदर्शन करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य जनता का ध्यान मूल समस्याओं से भटकाना है। प्रेसवार्ता को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, सरायकेला-खरसावां की जिलाध्यक्ष संगीता प्रधान व पश्चिमी सिंहभूम की राखी सुलेजा ने भी संबोधित किया।

धनबाद में छिनतई कांड का खुलासा, चार अपराधी गिरफ्तार, लैपटॉप-मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद

गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुई थी बड़ी वारदात, दो लाख रुपये की मांगी थी फिरौती

AGENCY DHANBAD : धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुई छिनतई की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा निवासी एक युवक से बाइक, लैपटॉप, मोबाइल और नगदी छीनने के साथ ही उससे दो लाख रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया था। मंगलवार को नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी एसपी) ऋत्विक श्रीवास्तव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना साहेबगंज रोड स्थित अपना अस्पताल के पास की है। जामताड़ा के नारायणपुर निवासी इरफान अंसारी को तीन बाइक पर सवार 6-7 अपराधियों ने निशाना बनाया। अपराधियों ने पहले बाइक की किस्त फेल होने का बहाना बनाकर उसे रोका और फिर उसकी बाइक, लैपटॉप, मोबाइल फोन और 22 हजार रुपये नकद छीन लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने पीड़ित से छीने गए सामान को लौटाने के बदले दो लाख रुपये की फिरौती मांगी और 4 मई को रकम देने का दबाव बनाया। पीड़ित द्वारा सूचना दिए जाने पर गोविंदपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान रेहान अंसारी, फरदीन अंसारी, राजू अंसारी और जावेद अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक हुंडई आई-20 कार, तीन बाइक, छीना गया लैपटॉप, सात मोबाइल फोन और 25 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपितों को अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, इस मामले में शामिल अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है और पूरे गिरोह के नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।

गिरफ्त में आरोपी व मामले की जानकारी देते सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव

मुनीडीह वाशरी हादसे की जांच शुरू

DHANBAD : पुटकी थाना क्षेत्र स्थित बीसीसीएल की मुनीडीह कोल वाशरी में 2 मई को हुए भीषण हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने शुरू कर दी है। प्रबंधन ने अलग-अलग स्तर पर दो जांच दल गठित किए हैं. क्षेत्रीय स्तर पर बनाई गई चार सदस्यीय टीम में वाशरी से जुड़े अधिकारी हैं। यह टीम मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंची और लगभग एक घंटे तक मौजूद कर्मियों से जानकारी हासिल की। टीम ने हादसे के वक्त की परिस्थितियों और कार्यप्रणाली से जुड़े हर पहलू की जानकारी जुटाने का प्रयास किया। जांच अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल वाशरी के लोडिंग प्वाइंट, जहां हादसा हुआ था, सभी प्रकार की गतिविधियां रोक दी गई हैं। लोडिंग प्वाइंट पर तैनात मजदूरों और कर्मचारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. जांच पूरी होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बीसीसीएल मुख्यालय ने भी एक टीम का गठन किया है, जो इस पूरे मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करेगी।

खूंटी के एक मकान में भीषण आग, छह कमरे जलकर राख

PHOTON NEWS KHUNTI : खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड 12 स्थित खूंटी टोली में सोमवार को देर रात भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस आगजनी में एक मकान के छह कमरे पूरी तरह जल गए। प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट होने की जताई जा रही है। घटना रात करीब साढ़े दस बजे की बताई जा रही है। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि घर के छह कमरे पूरी तरह खाक हो गए। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां तत्काल पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते कार्रवाई से आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। बताया जा रहा है कि मकान मालिक सहदेव महतो ने पूरे घर को किराए पर दे रखा था, जहां कई परिवार रहते थे। आगजनी से किरायेदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किरायेदार मुनिया देवी के अनुसार, उनकी करीब 10 लाख रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई, जिसमें शादी के लिए खरीदे गए गहने, नकदी और जरूरी सामान शामिल हैं। दूसरे किरायेदार राजलो डुंगडुंग ने बताया कि समोसा और गुलगुला बेचकर जमा की गई उनकी पूरी पूंजी, जमीन के कागजात और घरेलू सामान भी आग में जल गए। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। वार्ड सदस्य अनिल कच्छप ने बताया कि पीड़ितों को आपदा प्रबंधन विभाग के तहत मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।

आग से क्षतिग्रस्त मकान के बाहर जुटी भीड़

आयोजन पलामू प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी पहुंचे

मुखिया का बढ़ेगा मानदेय, विभाग कर रहा मंथन : दीपिका

AGENCY PALAMU : झारखंड में मुखिया प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पंचायती राज विभाग इस संबंध में देश के विभिन्न राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है, ताकि जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जा सके। यह बातें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सोमवार को पलामू प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन में कही।

मेदिनीनगर के गांधी स्मृति टाउन हॉल में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर तथा मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों के मुखिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले मुखियाओं को मंच से सम्मानित भी किया गया।

मौके पर दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पंचायत जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की पहली कड़ी हैं और गांव, पंचायत, प्रखंड से ही राज्य की पहचान बनती है।

उन्होंने कहा कि सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और प्रत्येक माह सुदृढ़ीकरण के लिए दी जा रही राशि से पंचायत भवनों की स्थिति में सुधार आया है। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायतों को प्राप्त राशि का उपयोग पेयजल, स्वच्छता और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं में किया जाए।

साथ ही अधिकारियों को कार्यों की सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अभावग्रस्त क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने पलामू क्षेत्र की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने गरीबी और सूखे का सामना किया है, इसलिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि मुखिया मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव आने पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेने को तैयार है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी, पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।

मुखिया सम्मेलन में मंचस्थ मंत्री दीपिका पांडेय सिंह व राधाकृष्ण किशोर

ड्यूटी पर चिकित्सकों की अनुपस्थिति नहीं की जाएगी बर्दाश्त : उपायुक्त

RAMGARH : डीसी ऋतुराज ने मंगलवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने ड्यूटी रोस्टर की जांच की और निर्देश दिया कि सभी चिकित्सक निर्धारित समय पर अपनी ओपीडी और वार्ड ड्यूटी में उपस्थित रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि राउंड के समय डॉक्टरों की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बायोमेट्रिक उपस्थिति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने मरीजों से बातचीत की। उन्होंने वार्डों का भ्रमण कर वहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल की ओर से दी जा रही चिकित्सा सेवाओं के संबंध में फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने यह देखा कि मरीजों को आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज का लाभ मिल रहा है या नहीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का लाभ सभी व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। दवाओं की स्टॉक रजिस्टर की जांच के दौरान डीसी ने डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिया कि वे केवल वही दवाएं लिखें जो अस्पताल में उपलब्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शत-प्रतिशत दवाएं अस्पताल से ही मिलनी चाहिए, मरीजों को बाहर से दवा खरीदना नहीं पड़े। अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ उन्होंने कर्मियों को अनुशासित रहने और मरीजों के साथ शालीन व्यवहार करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि मरीजों के इलाज में देरी या ड्यूटी से नदारद रहने वाले कर्मियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सदर अस्पताल में जांच करते डीसी ऋतुराज

BRIEF NEWS

वित्तीय विवरणों के गहन विश्लेषण के बाद करें निवेश : अरुल

RANCHI : द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल तत्वावधान में रांची के आईसीएआई भवन में मंगलवार को इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड फाइनेंसियल स्टेटमेंट एनालिसिस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मेजबानी आईसीएआई, रांची शाखा ने की। सेमिनार में काफी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भाग लिया। सेमिनार के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए इंस्टिट्यूट के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के सचिव और भीलवाड़ा राजस्थान के सीए निर्भिक गांधी शामिल हुए। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए निवेश के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।

अंचल के दाखिल-खारिज रिकॉर्ड गायब होने पर हाईकोर्ट सख्त

RANCHI : रांची के नामकुम अंचल से जुड़े दाखिल-खारिज के अभिलेख की सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध नहीं कराए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और मामले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी) से जांच कराने का आदेश दिया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालय से जमीन संबंधी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का गायब होना बेहद गंभीर मामला है। यह लापरवाही भी हो सकती है और साजिश भी। अदालत ने यह आशंका भी जताई कि कहीं गलत तरीके से दाखिल-खारिज तो नहीं किया गया, जिसके कारण जानबूझकर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

दुर्घटना पीड़ितों के न्याय को लेकर राज्यपाल से मिले आजसू के नेता

RANCHI : चतरा में एयर एंबुलेंस दुर्घटना के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को लेकर डॉ पार्थ पारितोष के नेतृत्व में आजसू पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुपालन के लिए पहल करने का अनुरोध किया गया। डॉ. पार्थ पारितोष ने बताया कि मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने आश्वस्त किया कि उक्त ज्ञापन को मुख्यमंत्री और राज्य सरकार तक अतिशीघ्र अग्रसारित किया जाएगा, ताकि इस गंभीर मामले में जल्द कार्रवाई हो सके। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यह बात डॉ. विकास के पिता ने अवगत कराई, जिन्होंने बताया कि तीन दिनों पूर्व मंत्री से दूरभाष पर हुई बातचीत में भी यही बात कही गई थी।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जांच में ओवरलोडेड मिलीं बसें

फाइन लगाकर छोड़ा, दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त किए जाएंगे वाहन

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। रांची जिला परिवहन कार्यालय ने ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई शुरू करते हुए कई स्कूल वैन की जांच की। यह कार्रवाई डीटीओ अखिलेश कुमार के निर्देश पर की गई। इस दौरान कई वाहन और वैन ओवरलोड पाए गए। जिसमें कैपेसिटी से अधिक बच्चे थे। बार-बार चेतावनी और दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद कई स्कूल वाहन संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। अधिक कमाई के लालच में बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा था। इसे गंभीरता से लेते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया और कई वाहनों का चालान काटा गया। जबकि कुछ वाहनों को जब्त किए जाने की सूचना मिली है।

स्कूल के बाहर प्राइवेट वैन की जांच करती पुलिस ● फोटोन न्यूज

छुट्टी के बाद चलाया गया सघन जांच अभियान

डीटीओ ने बताया कि सुबह के समय में चेकिंग नहीं की गई थी क्योंकि इससे बच्चों का स्कूल प्रभावित होता। लेकिन छुट्टी के बाद पूरे राजधानी में जबर्दस्त अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से सभी स्कूलों को नोटिस भी भेजा जाएगा। अगर चेतावनी के बाद भी ओवरलोडेड स्कूल वैन या बस पाए गए तो उनकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल बस की जांच करते डीटीओ ● फोटोन न्यूज

बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं : डीटीओ ने साफ कहा है कि यदि वाहन संचालक अपनी आदत में सुधार नहीं लाते हैं, तो आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग के दौरान ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, केराली स्कूल, जेवीएम श्यामली और बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल से जुड़े वाहनों की भी जांच की गई, जिनमें कई ओवरलोड पाए गए। अधिकारियों ने सभी वाहन चालकों और स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिया है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित और मानक अनुरूप वाहनों में ही भेजें। डीटीओ ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कृषि मंत्री ने फिश मार्केट का किया निरीक्षण, मिलीं गड़बड़ियां, जताई नाराजगी, कहा-

उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता

बाजार की संचालन प्रणाली को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एसओपी तैयार करने का निर्देश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राजधानी के धुर्वा स्थित शालीमार बाजार में संचालित हाइजेनिक फिश मार्केट और फिश फीड मील का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने व्यवस्थाओं में कई खामियां पाईं और इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर करने और व्यवस्था दुरुस्त करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि ये बाजार रांची और आसपास के क्षेत्रों के लिए मछली आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन भारी मात्रा में ताजी मछलियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

कृषि मंत्री ने बाजार की संचालन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एक स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने रेंटल एग्रीमेंट, किराया निर्धारण और दुकानदारों को दी जाने वाली सुविधाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि इन सुधारों से न केवल व्यापारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा।

फिश मार्केट का निरीक्षण करतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की व अन्य ● फोटोन न्यूज

6 मीट्रिक टन मछलियों की आपूर्ति

जानकारी के अनुसार इस फिश मार्केट में प्रतिदिन लगभग 6 मीट्रिक टन मछलियों की आपूर्ति होती है। ये मछलियां गेतलसूद डैम, चांडिल डैम, कोनार डैम, मैथन डैम, पंचेत डैम और मसानजोर डैम जैसे प्रमुख डैमों से लाई जाती हैं और यहां से विभिन्न बाजारों में वितरित की जाती हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने साफ-सफाई, रख-रखाव और स्वच्छता मानकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने फिश फीड मील के संचालन पर भी विशेष ध्यान देते हुए आपूर्ति और वितरण से संबंधित अद्यतन रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा।

किसानों से किया संवाद

मंत्री ने मत्स्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे किसानों से भी संवाद किया। किसानों ने बताया कि आगामी 15 से 30 दिनों में फिश फीड की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। इस पर मंत्री ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जिलों से मांग का आकलन कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि समय पर किसानों को आवश्यक फिश फीड उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना है कि झारखंड के प्रत्येक जिले में आधुनिक और सुव्यवस्थित मत्स्य बाजार विकसित किए जाएं। साथ ही मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

राज्य वित्त आयोग के लिए पद सृजन को सरकार ने दी मंजूरी

हाल ही में किया गया है पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन, सुचारू रूप से होगा कम

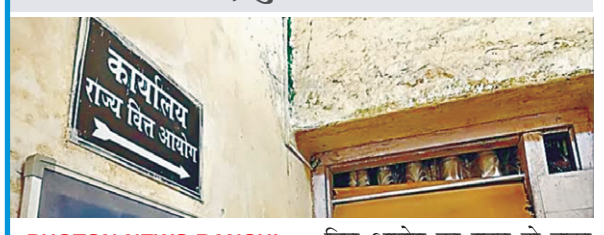

PHOTON NEWS RANCHI : हेमंत सरकार ने राज्य वित्त आयोग के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए पद सृजन को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार, पंचम राज्य वित्त आयोग के 27 जनवरी 2029 तक कार्यालय संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन किया जाएगा।

सरकार के इस फैसले के तहत पहले से स्वीकृत 15 पदों में संशोधन करते हुए जरूरत के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 18 पद किए जाएंगे। इसमें उपसचिव से लेकर विशेष रूप से निजी सहायक, टंकक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक और अनुसेवक जैसे पदों में बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि आयोग के कार्यों का निष्पादन सुचारू रूप से हो सके।

बता दें कि राज्य में वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रावधानों के तहत किया जाता है और अब तक प्रथम से लेकर पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है। हाल ही में पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके लिए यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन और उसकी अनुशंसाओं को विधानसभा में प्रस्तुत करना 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। संकल्प के अनुसार, कुछ पदों पर नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। इन कर्मियों का मानदेय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप होगा। इस प्रस्ताव को प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के बाद कैबिनेट से भी स्वीकृति ली गई थी। इस फैसले से राज्य वित्त आयोग के कामकाज में तेजी आने और पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों के बेहतर बंटवारे में मदद मिलने की उम्मीद है।

झारखंड में थाना प्रभारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू, डीजीपी ने किया उद्घाटन

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड के सभी जिलों के पुलिस थाना और ओपी प्रभारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने व जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण झारखंड पुलिस के तहत पुलिस ट्रेनिंग स्कूल झारखंड रांची में आयोजित किया गया। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरूआत की। इस दौरान उन्होंने प्रभारियों को आम जनता के साथ मिलकर बेहतर काम करने का मंत्र दिया।

राज्य में विधि-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए इस प्रशिक्षण को 5, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 और 29 मई को कुल 9 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक सत्र में अलग-अलग जिलों के थाना प्रभारी शामिल होंगे। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को पब्लिक के साथ व्यवहार, मीडिया ब्रीफिंग से जुड़े एसओपी, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अनिवार्य प्रावधान, सर्च और सीजर की प्रक्रिया, एफएसएल टीम की भूमिका, अभियोजन संबंधी पहलू तथा सीसीटीएनएस से जुड़े तकनीकी विषयों की जानकारी दी जा रही है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते पुलिसकर्मी ● फोटोन न्यूज

बेहतर पुलिसिंग के सिखाए गुर

अधिकारियों ने थाना प्रभारियों को व्यावहारिक अनुभव साझा करते हुए बेहतर पुलिसिंग के गुर सिखाए। साथ ही बताया कि इस पहल का उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जनविश्वास को मजबूत करना है ताकि आम जनता को बेहतर और संवेदनशील पुलिस सेवा मिल सके।

कार्ल मार्क्स की जयंती पर भाकपा कार्यालय में किया गया कार्यक्रम

RANCHI : भाकपा राज्य कार्यालय के सभागार में कार्ल मार्क्स की 208वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य सह जिला मंत्री अजय सिंह ने कहा कि कार्ल मार्क्स के दर्शन आज भी समाज के शोषित और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि मार्क्स ने विश्व को एक नई सोच दी और समाज में समानता व एकजुटता का संदेश दिया।

इंजीनियरों को धमकी देने वाले बबलू मिश्रा की भूमिका संदिग्ध : अजय शाह

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े कथित धमकी प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सवाल उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि इंजिनियरों को डराने-धमकाने वाले बबलू मिश्रा की भूमिका संदिग्ध है और उसे किसी प्रभावशाली संरक्षण का लाभ मिल रहा है। भाजपा ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। अजय साह ने कहा कि बबलू मिश्रा पर सरकारी इंजिनियरों को गाली-गलौज करने, अपमानित करने और अपने पसंदीदा ठेकेदारों को काम दिलाने का गंभीर आरोप है। उन्होंने मांग की कि मामले की तह तक जाने के लिए बबलू मिश्रा, उसके परिवार, स्टाफ और निजी सहायक (पीए) के कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाए। साथ ही ग्रामीण विकास कार्यालय में उसकी आवाजाही से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की भी जांच होनी चाहिए ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके।

जानकारी देते बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह व अन्य ● फोटोन न्यूज

पत्र भेजने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि चीफ इंजिनियर, अभियंता प्रमुख और विभागीय सचिव को भेजे गए पत्र पर 11 दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भाजपा का आरोप है कि बाबूलाल मरांडी द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही अधिकारी सक्रिय हुए, वह भी निष्पक्ष जांच के बजाय लीपापोती के उद्देश्य से। भाजपा ने संबंधित पत्र की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की है, ताकि उसकी सत्यता स्पष्ट हो सके।

मंथन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय समिति की हुई बैठक

मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों के डिजाइन में बदलाव की तैयारी

हर प्रकार से मरीजों को बेहतर सुविधा देने पर किया गया विचार-विमर्श

PHOTON NEWS RANCHI : राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डिजाइन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। मरीजों को बेहतर सुविधा देने और इलाज की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की पहली बैठक मंगलवार को अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अस्पतालों के समग्र ढांचे की समीक्षा पर जोर दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अपने विशेषज्ञ परामर्शदाताओं के साथ विस्तृत डिजाइन और योजनाओं का प्रस्तुतीकरण समिति के सामने करें। साथ ही भवन निर्माण विभाग और अन्य संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।

इस उच्चस्तरीय समिति में रिम्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के अनुभवी विशेषज्ञ शामिल हैं। इनमें कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल केयर, मेडिसिन, सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के वरिष्ठ चिकित्सक शामिल किए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य निमार्णाधीन और पहले से बने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों की डिजाइन व्यवस्था का गहन विश्लेषण करना है। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अस्पतालों में मरीजों के आवागमन और चिकित्सकीय कार्यप्रवाह को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया जाए। इससे इलाज की प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और अधिक प्रभावी हो सकेगी।

अधिकारियों के साथ बैठक करते अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ● फोटोन न्यूज

एक जगह होंगी महत्वपूर्ण इकाइयां

विशेष रूप से अस्पतालों की महत्वपूर्ण इकाइयों जैसे आईसीयू, सीसीयू, एचडीयू, ऑपरेशन थिएटर, आईपीडी, कैथ लैब, डायग्नोस्टिक और रेडियोलॉजी सेंटर के सही स्थान निर्धारण पर ध्यान दिया जा रहा है। इन इकाइयों की स्थिति ऐसी हो कि मरीजों को कम से कम समय में जरूरी सेवाएं मिल सकें। समिति को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह मौजूदा डिजाइन का परीक्षण करे और जहां जरूरत हो वहां संशोधन या पुनर्रचना के लिए स्पष्ट सुझाव दे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज परिसरों में एकेडमिक भवन, आवासीय परिसर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी आधारभूत सुविधाओं के बेहतर विस्तार और संतुलित विकास पर भी विचार किया जाएगा।

मारवाड़ी युवा मंच के सेवा अभियान में छाछ व ठंडे पानी का वितरण

RANCHI : भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मारवाड़ी युवा मंच, रांची समर्पण शाखा द्वारा 'प्यार बांटते चलो' नारे के तहत चलाए जा रहे '15 दिन 15 जनसेवा' अभियान के अंतर्गत मंगलवार को बकरी बाजार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राहगीरों और श्रद्धालुओं के बीच ठंडी छाछ और शीतल जल का वितरण किया गया। गर्मी से परेशान लोगों को इस सेवा कार्य से काफी राहत मिली। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए सकारात्मक संदेश देने वाला कदम बताया। कार्यक्रम का संचालन शाखा सदस्य कोमल पोद्दार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने छाछ और ठंडा पानी ग्रहण किया।

लॉकडाउन के दौरान पेड़ कटाई मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

PHOTON NEWS RANCHI : वर्ष 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान झारखंड के कई जिलों में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़े अवमानना याचिका मामले की सुनवाई सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय में हुई।

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में एडीजी सीआईडी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा।

सरकार ने अदालत को बताया कि मामले की जांच में प्रगति हुई है। एक नामजद आरोपी महाराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे आरोपी मोहाफिज अंसारी के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति मिल चुकी है।

पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि इस मामले में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंजर, वन गार्ड और अन्य वन अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है, जिसके कारण जांच में देरी हुई। साथ ही, दो वन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और एक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में जांच की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को निर्धारित की गई है।

डॉक्टर के चैंबर में घुसकर मारपीट, इलाज में लापरवाही के आरोप पर हुआ हंगामा

टॉन्सिल का ऑपरेशन कराया था मरीज, लेकिन नौ दिन बाद भी हो रही थी ब्लीडिंग

- तबीयत ठीक नहीं होने पर एक सप्ताह बाद डॉक्टर ने टीएमएच कर दिया था रेफर, परिजन नाराज

PHOTON NEWS JSR: साकची स्थित मेडिसिस्ट ईएनटी एंड जनरल हॉस्पिटल में मंगलवार को दोपहर में इलाज को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा और मारपीट हो गई। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सक डॉ. बी. प्रधान के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आई हैं।

घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही साकची थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि मारपीट करने वाले युवक मौके से फरार हो गए। डॉ. प्रधान ने आरोप लगाया कि एक मरीज के परिजन जबरन उनके चैंबर में घुस आए और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि करीब 30 युवक उनके कमरे में घुसे और टीएमएच में हुए इलाज का पूरा खर्च उठाने की धमकी देने लगे।

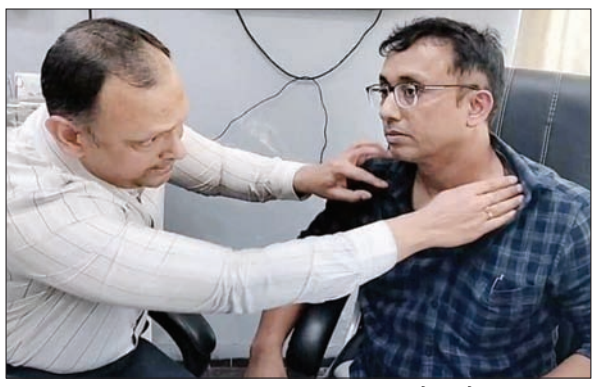
डॉ. बी. प्रधान की चोट देखते आईएमए के महासचिव डॉ. सौरभ चौधरी (बाएं)

परिजनों का आरोप- लापरवाही से बिगड़ी हालत

मरीज राजहंस कुमार के परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद सही इलाज नहीं हुआ, जिससे लगातार ब्लीडिंग होती रही और मरीज की हालत गंभीर हो गई। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए टीएमएच में हुए इलाज का खर्च मेडिसिस्ट अस्पताल से दिलाने की मांग की है।

आईएमए ने अख्तियार किया कड़ा रुख

घटना की सूचना मिलने पर आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) के महासचिव डॉ. सौरभ चौधरी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि गलत इलाज या फीस को लेकर डॉक्टरों के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। आईएमए ने चेतावनी दी है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संगठन कदम उठाएगा। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही जा रही है।

डॉक्टर के अनुसार, 24 अप्रैल को मरीज को टॉन्सिल ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था। ऑपरेशन के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 29 अप्रैल को दोबारा ब्लीडिंग की शिकायत के साथ मरीज वापस आया।

इलाज के बाद स्थिति नियंत्रित हुई और 3 मई तक मरीज अस्पताल में भर्ती रहा। हालांकि 3 मई को फिर से ब्लीडिंग शुरू होने पर मरीज को टीएमएच रेफर किया गया, जहां फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

त्रिपक्षीय वार्ता बेनतीजा 11 से गुवा में चक्का जाम का एलान

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा स्थित सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) की लौह अयस्क खदान में रोजगार को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गहरा गया है। 18 गांवों के ग्रामीणों और सेल प्रबंधन के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका, जिसके बाद ग्रामीणों ने 11 मई से खदान को अनिश्चितकालीन बंद करने का निर्णय लिया है। बताया गया कि 18 गांवों के मुंडा-मानकी प्रतिनिधियों ने 20 अप्रैल को स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर खदान का संचालन ठप कर दिया था। ग्रामीणों की मुख्य मांग गुवा सेल परियोजना में कम से कम 500 स्थानीय लोगों को रोजगार देने की थी। इस संबंध में पूर्व में आवेदन भी दिया गया था, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं करने का आरोप लगाया गया। हालांकि, उसी दिन सेल अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि 5 मई को इस मुद्दे पर बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद खदान का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया था। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 5 मई की शाम को गुवा स्थित सेल के ऑफिस में बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, 18 गांवों के मुंडा-मानकी और अन्य ग्रामीण प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में रोजगार के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन प्रबंधन ने केवल 25 लोगों को रोजगार देने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर मुंडा-मानकी प्रतिनिधियों और मधु कोड़ा ने बैठक का बहिष्कार कर दिया।

घाटशिला कॉलेज को विस्तार के लिए चाहिए अतिरिक्त भूमि

बैठक के दौरान उपस्थित अंचल अधिकारी, प्राचार्य व अन्य ● फोटोन न्यूज

GHATSILA : घाटशिला कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरके चौधरी मंगलवार को अंचल अधिकारी निशात अम्बर से उनके कार्यालय में मिले। प्राचार्य के साथ कॉलेज के वरीय शिक्षक डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संदीप चंद्र व डॉ. महेश्वर प्रमाणिक भी उपस्थित थे। प्राचार्य ने बताया कि घाटशिला कॉलेज का विस्तार करने के लिए अलग कैंपस बनाना होगा, जिसके लिए अतिरिक्त भूमि चाहिए। इसका प्रतिवेदन तैयार कर उन्होंने कोल्हान विश्वविद्यालय को दिया था। वहां से झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र भेजकर विभागीय सहयोग की मांग की गई। तत्पश्चात निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को घाटशिला कॉलेज के लिए अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने संबंधी पत्र भेजा गया। अंचल अधिकारी निशात अम्बर एवं अंचल निरीक्षक लखिन्द्र मांझी ने प्राचार्य को बताया कि घाटशिला कॉलेज के लिए बैतालपुर मौजा अंतर्गत हेंदलजोड़ी पंचायत में 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि चिह्नित की गई है। अंचल अधिकारी को प्राचार्य ने बताया कि 1975 में तत्कालीन बिहार के राज्यपाल सचिवालय द्वारा घाटशिला कॉलेज को लीज में मिली भूमि का सत्यापन करा कर उक्त भूमि का लीज नवीकरण कराने का भी आग्रह किया था। इस पर अंचल अधिकारी ने सहमति व्यक्त करते हुए प्राचार्य से कहा कि वह इस प्रस्ताव को दोबारा कार्यालय में जमा करा दें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र की जा सके।

समाचार सार

हाटगम्हरिया के बीडीओ सालकु हेम्ब्रम का निधन

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत हाटगम्हरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी सालकु हेम्ब्रम (49) का मंगलवार को सुबह 3 बजे इलाज के दौरान निधन हो गया। जानकारी के अनुसार, सालकु हेम्ब्रम कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और उनका जमशेदपुर स्थित टीएमएच में इलाज चल रहा था। निधन की सूचना मिलते ही जिला व प्रखंड मुख्यालय में शोक छा गया। उपायुक्त मनीष कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों-कर्मियों ने समाहरणालय परिसर में दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। स्व. हेम्ब्रम घाटशिला के दामपाड़ा क्षेत्र स्थित असना पंचायत अंतर्गत छोटा धातिका गांव के निवासी थे। उन्होंने प्रशासनिक करियर की शुरूआत बहरागोड़ा से शुरू किया था, इसके बाद चाईबासा में जेलर के पद पर रहे।

3200 किलो जावा महुआ व 60 लीटर देसी शराब जब्त

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर मंगलवार को उत्पाद विभाग और चक्रधरपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पकुआबेड़ा नदी किनारे स्थित गांव में छापेमारी की गई। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि नदी किनारे अवैध रूप से देसी शराब का निर्माण किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान मौके से 3200 किलो जावा महुआ और 60 लीटर तैयार देसी शराब बरामद की गई। इसके साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल की जा रही 6 भट्ठियों को भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब कारोबार का संचालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक ने बताया कि फरार अभियुक्त की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चक्रधरपुर थाना की पुलिस भी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय योगगुरु अंशु सरकार वियतनाम में सम्मानित

JAMSHEDPUR : अंतरराष्ट्रीय योगगुरु अंशु सरकार को चार दिवसीय वियतनाम दौरे के दौरान विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान योग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और वैश्विक स्तर पर योग के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया गया। वियतनाम के काऊ लांच सिटी के डांगथाप में संस्था हील योगा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अंशु सरकार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस दौरान संस्था के मास्टर रविशंकर सहित अन्य पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। गौरतलब है कि अंशु सरकार से प्रशिक्षित कई विद्यार्थी वियतनाम में योग का व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। ये प्रशिक्षु स्थानीय लोगों को योग की शिक्षा देकर इस प्राचीन भारतीय परंपरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। कदमा शास्त्रीनगर निवासी प्रशांत राज समेत अन्य शिष्यों ने भी अपने गुरु को सम्मानित किया।

जोजोबेड़ा में 26.59 लाख की तीन योजनाओं का शिलान्यास

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने मंगलवार को टेल्को के विभिन्न क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग की निधि से स्वीकृत तीन जनहितकारी योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं पर कुल 26 लाख 59 हजार रुपये की लागत आएगी। विधायक ने जोजोबेड़ा बस्ती में सड़क निर्माण कार्य, जोजोबेड़ा सामुदायिक भवन मैदान में हाईमास्ट लाइट एवं जोजोबेड़ा सामुदायिक भवन के समीप डीप बोरिंग अधिष्ठापन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि विधानसभा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र के विकास के लिए लगातार योजनाएं स्वीकृत कराई जा रही हैं और लोगों की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी जनहित से जुड़ी कई नई योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। शिलान्यास के दौरान सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार, विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव, भाजपा के टेल्को मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, राम अवतार गुप्ता, महादेव गुप्ता, रजनीश कुमार समेत कई स्थानीय गणमान्य नागरिक एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पूर्व जिप सदस्य किशोर यादव समेत पांच आरोपी हुए बरी

कोर्ट परिसर में मुकदमे के आरोपी व अधिवक्ता ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर में वर्ष 2013 में चर्चित धरना-प्रदर्शन और हंगामा मामले में जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व जिला पार्षद और पूर्व झामिमो नेता किशोर यादव सहित पांच आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में राहुल सिंह, धनंजय सिंह, डीएन सिंह और आरबी शरण भी शामिल थे, जिन्हें अदालत ने दोषमुक्त घोषित किया। यह मामला 4 जनवरी 2013 का है, जब जन समस्याओं को लेकर सैकड़ों सियासी कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई थी। घटना के बाद डीसी ऑफिस के लिपिक अलखेन खलको ने बिष्टुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष केवल तीन गवाह ही प्रस्तुत कर सका, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने मजबूत दलीलें रखीं। अंततः अदालत ने पाया कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, जिसके आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

बाइक से घर लौट रहे ट्रांसपोर्ट कारोबारी की सड़क हादसे में मौत

JAMSHEDPUR : ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े कारोबारी अजय दुबे (41) की सोमवार को देर रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परसुडीह थाना अंतर्गत कीताडीह के ग्वाला पट्टी निवासी अजय दुबे के साथ यह घटना बमार्माइंस स्थित लालबाबा फाउंड्री के पास हुई। बताया जाता है कि वे सड़क पर अचानक आए कुत्ते को बचाने में पास खड़ी ट्रेलर से टकरा गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अजय दुबे को तुरंत इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि अजय दुबे सोमवार को ही चाकुलिया से ट्रेन के जरिए जमशेदपुर लौटे थे। घर पहुंचने के बाद वे अपनी बाइक से गोलमुरी स्थित दोस्तों से मिलने गए थे। देर रात जब वे घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। मंगलवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

ब्लिंकिट के दफ्तर में घुसकर युवकों ने की मारपीट, पुलिस से भी धक्का-मुक्की

मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज

PHOTON NEWS JSR: सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में केनरा बैंक के पास स्थित ब्लिंकिट के डिलीवरी कार्यालय में सोमवार को रात करीब 12 बजे बाइक सवार चार युवक पहुंचे और बिना किसी स्पष्ट कारण के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिससे कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी भयभीत हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी युवक नशे की हालत में थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर हालात को काबू में किया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने चारों युवकों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है और घटना के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।

टाटानगर स्टेशन पर धराया पॉकेटमार वायरल वीडियो ने खोल दी पोल

PHOTON NEWS JSR: टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक शातिर पॉकेटमार को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और जीआरपी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को देखने के बाद की गई। इसमें आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर पॉकेटमारी का प्रयास करता नजर आया था। गिरफ्तार आरोपी ताबिश मानगो की आजाद बस्ती का रहने वाला है। उसका स्थायी पता बिहार के गया जिले में है। गौरतलब है कि 2 मई को फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि टाटानगर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास एक युवक यात्रियों की भीड़ में चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां फौरन हरकत में आ गईं। आरपीएफ व जीआरपी की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपी को रविवार शाम स्टेशन परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी का एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रेल थाना टाटानगर को सौंप दिया गया है। पुलिस अब उसके आपराधिक रिकॉर्ड और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने पहले कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान अपने सामान और कीमती वस्तुओं पर विशेष ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत आरपीएफ या रेलवे पुलिस को दें।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

अधिक दवा सेवन से महिला की मौत

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा प्रखंड के सीटेर गांव निवासी महिला सुंदरी डाडका (45) की अधिक दवा सेवन से तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, सुंदरी डाडका पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। सोमवार शाम को उसने घर में रखी दवा गलती से अधिक मात्रा में सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। तबीयत गंभीर होते देख परिजन उसे तुरंत गोइलकेरा अस्पताल ले गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया। रात में सदर अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन रात करीब 1.30 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मंगलवार को पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव के पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की। परिजनों ने बताया कि मृतिका बीमार थी और दवा का सेवन कर रही थी। सोमवार शाम को भूलवश उसने दवा की अधिक खुराक ले ली, जिससे उसकी जान चली गई।

गुवा के 500 परिवार पुनर्वास की आस में पहुंचे डीसी ऑफिस

एडीसी प्रवीण केरकेट्टा को ज्ञापन सौंपते विस्थापित ● फोटोन न्यूज

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा क्षेत्र के विस्थापितों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं एवं पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं को लेकर उपायुक्त मनीष कुमार से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा। डीसी ने मामले की गंभीरता देखते हुए एडीसी प्रवीण केरकेट्टा को विस्थापितों की मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। विस्थापितों ने बताया कि नोवामुंडी प्रखंड अंतर्गत खदान के विस्तारीकरण के क्रम में प्रबंधन द्वारा रामनगर डीपासाई, नानक नगर, पुट साइडिंग तथा जाटा हाटिंग पंचायत (गुवा पूर्वी-पश्चिमी) के निवासियों को अन्यत्र विस्थापित करने का प्रस्ताव है। अब तक प्रबंधन द्वारा केवल 184 परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, जबकि लगभग 500 परिवार अब भी विस्थापन की सूची से बाहर हैं। विस्थापितों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि छूटे हुए परिवारों का पुनः सर्वे कर सरकारी नियमानुसार पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि जब तक सभी परिवारों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक विस्थापन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

समस्या पीएम आवास योजना के लाभुकों संग बैठक में शामिल हुए विधायक, प्रोजेक्ट हेड और डीएमसी

31 तक लाभुकों को नहीं मिली चाबी तो 1 जून से अनशन : सरयू

PHOTON NEWS JSR : बिरसानगर में निमार्णाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटित मकानों की चाबी लाभुकों को देने के मुद्दे पर मंगलवार को जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय के बिष्टुपुर स्थित आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में 75 से ज्यादा लाभुक आए थे। जेएनएसी के उप-नगर आयुक्त कृष्ण कुमार और जुडको के प्रोजेक्ट मैनेजर धनंजय कुमार भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कहा गया कि चूंकि प्रधानमंत्री आवासीय योजना क्षेत्र में सड़क, नाली, ड्रेनेज आदि का काम अधूरा है, लिहाजा 31 मई तक इन कार्यों को पूरा करने के लिए और समय चाहिए। विधायक ने कहा कि सड़क, नाली, ड्रेनेज आदि का काम प्रारंभ हो जाए तो वह मंत्री से मिलेंगे और लाभुकों को चाबी देने के लिए कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, तो वह 1 जून से अनशन पर बैठ जाएंगे। बैठक की शुरूआत में ही जदयू विधायक सरयू राय ने लाभुकों को बताया कि इन दो दिनों में वह मंत्री से मिले और लाभुकों की परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। चूंकि यह प्रोजेक्ट जुडको के पास है। मकान वही बना रहा है। अभी कई कमियां हैं। सड़क, नाली, ड्रेनेज आदि कुछ बना नहीं है। लिहाजा, जुडको ने जेएनएसी को प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं किया। इस पर प्रोजेक्ट मैनेजर धनंजय कुमार ने बताया कि बाथरूम और किचन का पानी निकालने के लिए ड्रेन बनना है। पहले योजना स्वीकृत नहीं हुई थी। अब फाइनल स्टेज में योजना है। ड्रेन का टेंडर फाइनल हो चुका है। जल्द ही काम दिया जाएगा। एक माह में ड्रेन का काम पूरा हो जाएगा। सड़क का पैसा सैंक्शन होना है। हो जाता है तो ठीक, अन्यथा वहां फ्लाईऐश बिछवाएंगे, ताकि लोगों को आने-जाने में दिक्कत न हो। आपके दबाव के कारण कार्य प्रगति पर है, फिर भी इसमें एक माह लगेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर की इस बात पर लाभुक भड़क गए। एक लाभुक ने कहा कि आप लोग 2023 में ही गृहप्रवेश करवा रहे थे। अब 2026 आ गया है। कई लोग मर चुके हैं। हम लोगों में से भी कितने बचेंगे, पता नहीं। हमलोगों को आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है। आठ साल हो गए, लेकिन हमें मकान नहीं मिला। उप-नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि जुडको जब तक सड़क, नाली, ड्रेन का काम पूरा नहीं करता, तब तक हम लोग उसे हैंडओवर करने को नहीं कह सकते। प्रोजेक्ट जब तक पूरा नहीं हो जाता, उसे जेएनएसी कैसे अपने हाथों में ले सकती है। प्रोजेक्ट पूरा होने में कम से कम एक माह लगेगा। इसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस पर कई लाभुक भड़क गए। लाभुकों का कहना था कि जेएनएसी उन्हें बार-बार आश्वासन देता है। कभी सही तरीके से जवाब नहीं मिलता। लाभुक इस बात पर अड़ गए कि आप लोग एक तारीख बताएं। लिख कर दें। हमलोग जब इतना इंतजार कर चुके तो थोड़ा इंतजार और कर लेंगे। लेकिन, हमें लिखित में तारीख चाहिए। इस पर कहा गया कि प्रोजेक्ट तैयार होने में 31 मई तक का वक्त लग जाएगा। अंत में यही तय हुआ कि 31 मई तक सड़क, नाली और ड्रेन बन कर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद एक समारोह तय कर लाभुकों को चाबी सौंपी जाएगी। उसी वक्त सरयू राय ने कहा कि अगर 31 मई तक प्रोजेक्ट तैयार नहीं होता, लाभुकों को उनके मकान की चाबी नहीं दी जाती तो वह 1 जून से अनशन पर बैठ जाएंगे।

विधायक सरयू राय से गुहार लगाती महिला ● फोटोन न्यूज

आप हमें चाबी दें, अपना काम करते रहें

मीटिंग में लाभुकों ने मांग रखी कि अथॉरिटी उन्हें चाबी दे और जो भी काम बकाया है, उसे पूरा करें। लाभुकों ने प्रोजेक्ट मैनेजर और उप नगर आयुक्त से कहा कि कोई घर में घुसेगा नहीं। लेकिन, चाबी उन्हें मिलनी चाहिए। लाभुकों ने यह भी कहा कि उन सभी ने 6 मई को गृहप्रवेश की तैयारी कर रखी है। इस पर उप नगर आयुक्त ने कहा कि आप अपने मन से कोई भी काम कैसे कर सकते हैं। इसका बाकायदा एक सिस्टम है। अभी काम बचा है। काम पूरा हो जाएगा, तब जुडको प्रोजेक्ट को जेएनएसी को हैंडओवर करेगा। उसके बाद उद्घाटन होगा, तब आपको चाबी मिलेगी।

BRIEF NEWS

अवैध खनन पर प्रशासन की सख्ती

KISHANGANJ : जिले में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सघन अभियान चलाया। जिलाधिकारी विशाल राज एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के संयुक्त निर्देश पर बेलवा, टेंगरमारी से पोठिया डोक नदी क्षेत्र में छापेमारी की गई। अभियान के दौरान थर्मोकॉल से बनी नावों के जरिए अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसी दर्जनों नावों को मौके पर ही नष्ट कर दिया, जिनका उपयोग अवैध खनन में किया जा रहा था। इस दौरान अवैध खनन में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

टोल के नाम पर अवैध वसूली करने वाला गिरफ्तार

EAST CHAMPARAN : जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में सड़क पर चलने वाले वाहनों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 'टॉल टैक्स' के नाम पर लूट मचा रहे एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई हरसिद्धि दुर्गा मंदिर के समीप की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, हरसिद्धि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दुर्गा मंदिर के पास कुछ असामाजिक तत्व सड़क से गुजरने वाले वाहनों को रोककर जबरन पैसे की वसूली कर रहे हैं। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से अवैध वसूली कर रहे मो. हसमुद्दीन को दबोच लिया। वह हरसिद्धि थाना क्षेत्र के दुदही गांव का रहने वाला है। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध वसूली के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फर्जी टिकट और नकद पैसे बरामद किए गए हैं। वह खुद को टोल कर्मी बताकर भोले-भाले वाहन चालकों से पैसों की उगाही कर रहा था। हरसिद्धि पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है जो इस तरह के अवैध कार्यों में संलिप्त हैं। गिरफ्तार आरोपी को कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेशी के लिए भेज दिया गया है। जिला प्रशासन व पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कहीं भी अवैध वसूली की शिकायत हो तो तुरंत नजदीकी थाने को सूचित करें।

सिवान में पंप पर हमला, मैनेजर व नोजल मैन से मारपीट

SIWAN : शहर में पेट्रोल संकट ने हिंसक रूप ले लिया, जब मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मैरवा रोड स्थित श्रीनगर के कुमार पेट्रोल पंप पर दो युवकों ने पेट्रोल लेने को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा किया। आरोप है कि युवकों ने लाइन में खड़े होने से इनकार करते हुए पहले गाली-गलौज की और फिर मैनेजर व नोजल मैन के साथ मारपीट कर दी। घटना के दौरान उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप पर ईंट-पत्थर भी फेंके, जिसमें नोजल मैन श्रीराम कुमार और मैनेजर आशीष कुमार घायल हो गए। दोनों का स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया। मैनेजर आशीष कुमार ने बताया कि मंगलवार को शहर के लगभग आधे पेट्रोल पंप ड्राई होने के कारण बंद थे, जिससे उनके पंप पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। स्थिति को संभालने के लिए पहले पुलिस बल भी तैनात था, लेकिन शाम करीब 4:30 बजे पुलिस के हटते ही बुलेट सवार दो युवक पहुंचे और बिना लाइन के पेट्रोल देने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर दोनों युवक भड़क उठे और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मियों पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हंगामे के बीच लूटपाट की कोशिश भी की गई, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ के कारण वे सफल नहीं हो सके। घटना के बाद दोनों युवक अपनी बाइक छोड़कर चारदीवारी फांदकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस ने मौके से बाइक जब्त कर ली और दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कर्मियों के अनुसार, सुबह से ही पेट्रोल के लिए लंबी कतार लगी थी। शहर में कई पंप बंद होने के कारण लोग डीजल और पेट्रोल के लिए भटकते रहे, जिससे हालात और बिगड़ गए। पुलिस घटना की सच्चाई जानने के लिए पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वारदात में हिरासत में लिए गए युवकों के अलावा और कौन-कौन शामिल थे।

24 घंटे में आंधी-बारिश व आकाशीय बिजली से 24 लोगों की चली गई जान

आश्रितों को सरकार देगी 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

PHOTON NEWS PATNA : राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सोमवार शाम से देर रात तक तेज आंधी-बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 07 बच्चों समेत कुल 24 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटे बेहद संवेदनशील बताए हैं। राज्य सरकार ने मृतक आश्रित परिवारों को तुरंत 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा गयाजी में 6 लोगों जान गई है। वहीं, पूर्वी-पश्चिमी चंपारण में भी 6 लोगों की मौत हुई है। बीते सोमवार को देर शाम अचानक मौसम ने भयावह रूप ले लिया। आसमान काले बादलों से घिर गया। तेज आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। राज्यभर में बिजली गिरने और पेड़ गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आकाशीय बिजली व आंधी-तूफान से हुई मौत पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने मृतक आश्रित परिवारों को तुरंत 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटे बेहद संवेदनशील बताए हैं। मंगलवार को 18 जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और अरवल में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, पटना समेत 10 जिलों में रेड अलर्ट लागू है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

किस जिले में कितनी मौत

- पटना जिले के बाढ़ में पेड़ और दीवार गिरने से 2 की मौत
- पूर्वी चंपारण में 6 लोगों की मौत
- गयाजी में 6 की मौत
- औरंगाबाद में व्रजपात से 3 की मौत
- रोहतास जिले में 1 की मौत
- वैशाली के लालगंज में एक महिला और संदेश थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत
- सीतामढ़ी में 2 महिला की मौत
- नालंदा में पेड़ टूटने से 2 की मौत।

सारण में बाढ़ से सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू

SARAN : मानसून के आगमन से पूर्व बाढ़ की किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिले के 10 संवेदनशील स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य जारी है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को पुराने अनुभवों के आधार पर संवेदनशील बिंदुओं को चिन्हित करने और तटबंधों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से अति संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन सर्वे का उपयोग किया जा रहा है। सभी बाढ़ निरोधी कार्यों को 15 जून तक और सामग्रियों के भंडारण को 1 जून तक पूर्ण करने की समय सीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई हेतु मकेर और सोनपुर में अस्थाई कैंप कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही आश्रय स्थलों, कम्युनिटी किचन और पशु चारे के लिए आपूर्तिकताओं का चयन कर लिया गया है। पशुपालन विभाग के पास 44 प्रकार की दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने पथ निर्माण विभाग को पुल-पुलियों के वेंट्स की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि जल निकासी बाधित न हो।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अपर समाहर्ता सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि एसडीओ और सीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

दबंगों ने अति पिछड़ा परिवार पर किया हमला, हुआ जख्मी

NAWADA : नवादा जिले के गोविंदपुर थाने के धनपुरी गांव में दबंग ने अति पिछड़ा समाज के राजेंद्र राम के घर पर शस्त्रों के साथ हमला कर चार परिवार को जख्मी कर दिया। जिसे गंभीर हालत में पावापुरी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। गोविंदपुर के थाना प्रभारी सहित नवादा के एसपी को मंगलवार को भेजे गए आवेदन में राजेंद्र राम ने कहा कि दबंग जाति के बालन यादव, उसका पुत्र मिथिलेश यादव तथा प्रतिमा देवी बराबर जाति सूचक शब्द कहकर घर पर चढ़कर गालियां दिया करती है। इस बार जैसे ही गालियां देने से मना किया कि सभी ने मिलकर शस्त्रों से हमला कर दिया, जिसमें राजेंद्र राम सहित सुलेखा देवी, शिवानी कुमारी तथा सौरभ कुमार घायल हो गए। राजेंद्र राम को गंभीर हालत में गोविंदपुर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज पवापुरी भेज दिया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बताई जाती है। इस घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। एसपी से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राजेंद्र राम के पुत्र प्रिंस ने बताया कि दबंगों द्वारा भूमि कब्जा को लेकर बराबर गालियां दी जाती है विरोध करने पर बराबर मारपीट किया करते हैं। इस बार जानलेवा हमला कर पूरे परिवार को खत्म कर देने का प्रयास किया गया।

अस्पताल में इलाजरत घायल

किशनगंज में 48 घंटे के भीतर बच्ची की हत्या का हुआ उद्भेदन, चाची ही निकली कातिल

कोढ़ोबारी थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में मकई के खेत से मिली थी लाश

AGENCY KISHANGANJ : जिले के कोढ़ोबारी थाना क्षेत्र में 08 वर्षीय बच्ची शहरानी उर्फ साली प्रवीण की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सफल उद्भेदन कर लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में मृतका की चाची (बड़ी मां) हैरूण निशा को ही आरोपी पाया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दुर्गापुर गांव में मकई के खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस संबंध में कोढ़ोबारी थाना कांड संख्या-71/26 के तहत बीएनएस की धारा 103(1)/238 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने 03 मई को घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले के शीघ्र उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 मंगलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) का गठन किया। टीम ने मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लगातार छापेमारी और पूछताछ की। जांच के क्रम में मृतका की चाची हैरूण निशा का व्यवहार संदिग्ध पाया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसका बेटा और मृतका के बीच झगड़ा हो रहा था, जिससे वह गुस्से में आ गई और बच्ची को थप्पड़ मारकर धक्का दे दिया। इससे बच्ची गिरकर बेहोश हो गई। बाद में पकड़े जाने के डर से उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने शव को घर में छिपाकर रखा और शाम होने पर मच्छरदानी के कपड़े से मुंह ढंककर मकई के खेत में ले जाकर छुपा दिया। घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए खून से सने कपड़े, मच्छरदानी का टुकड़ा तथा घटनास्थल से टूटा हुआ चप्पल पुलिस ने बरामद कर लिया है। एफएसएल टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी परिवार की सदस्य होने के कारण जांच को भटकाने की कोशिश कर रही थी और बार-बार बयान बदल रही थी।

पीड़ित के घर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी

ऑपरेशन 'नन्हे फरिश्ते' के तहत दस नाबालिगों को बचाया, दो गिरफ्तार

BHAGALPUR : यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मानव तस्करी एवं शोषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे के मालदा मंडल की रेलवे सुरक्षा बल ने बड़हरवा रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन 'नन्हे फरिश्ते' के अंतर्गत सफल अभियान चलाया। यह अभियान मनीष कुमार गुप्ता मंडल रेल प्रबंधक मालदा के मार्गदर्शन तथा आशिम कुमार कुल्लू मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ/मालदा के पर्यवेक्षण में संचालित किया गया, जो मंडल की संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बरहरवा रेलवे स्टेशन पर नियमित जांच के दौरान आरपीएफ कर्मियों ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर प्लेटफॉर्म संख्या 01 पर चार नाबालिग लड़कों के साथ दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। पूछताछ करने पर पता चला कि नाबालिगों को बिना उचित अनुमति रोजगार के बहाने राज्य के बाहर ले जाया जा रहा था। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने चारों नाबालिग लड़कों को सुरक्षित बरामद किया तथा इस कृत्य में संलिप्त दो व्यक्तियों को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि नाबालिगों को रोजगार एवं मजदूरी का झूठा प्रलोभन देकर बहलाया-फुसलाया जा रहा था। एक अन्य घटना में बड़हरवा रेलवे स्टेशन के परिसंचरण क्षेत्र में छह नाबालिग बच्चे (चार लड़के एवं दो लड़कियां) बिना अभिभावक के संदिग्ध अवस्था में पाए गए।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी व बरामद बच्चे

पशु तस्करी के खिलाफ अभियान में 5 वाहन समेत 146 मवेशी जब्त, सात गिरफ्तार

ARARIA : अररिया जिला पुलिस की ओर से अवैध मवेशी तस्करी के खिलाफ समकालीन अभियान चलाया गया। जिसके तहत नरपतगंज, फारबिसगंज, टाउन थाना और सिमराहा थाना पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में चार कंटेनर डीसीएम, एक पिकअप वाहन, 146 मवेशी के साथ सात तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी एसपी जितेन्द्र कुमार ने दी। एसपी ने बताया कि अवैध मवेशी तस्करी के खिलाफ जिला में समकालीन अभियान चलाया गया था।जिसके तहत नरपतगंज थाना पुलिस ने एक डीसीएम कंटेनर में लदे 28 मवेशी जब्त किए गए।जबकि मामले में कटिहार जिला के कोढ़ा थाना क्षेत्र के सिमराही के रहने वाले 26 वर्षीय मो.सफीक पिता मो. कलाम और पश्च बंगाल के मालदा के रतवा गांव के 25 वर्षीय गुलाम एसधानी पिता अब्दुल सलाम को गिरफ्तार किया गया। फारबिसगंज थाना पुलिस के द्वारा दो डीसीएम कंटेनर में लदे 82 मवेशी के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

नवादा में बच्चों की सुरक्षा को ले स्कूली वाहनों पर लगा जुर्माना

NAWADA : जिले में मंगलवार को स्कूल वाहनों की जांच कर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया गया है। जांच के दौरान ओवरलोडिंग, फिटनेस नहीं होना, इंश्योरेंस नहीं होना, प्रदूषण प्रमाणपत्र गायब होना और परमिट शर्तों के उल्लंघन जैसे मामले सामने आए। राजश्री कृष्ण इंटरनेशनल स्कूल, अकौना की बस बीआर 52 पी-0539 पर ओवर पैसेंजर और परमिट उल्लंघन में 15,300 का जुमार्ना लगाया गया। माउंट मिराडे किड्स स्कूल, नवादा की बस बीआर 27 बी-0354 पर ओवरलोडिंग और परमिट गड़बड़ी में 10,800 का चालान काटा गया। आवासीय शिशु ज्ञान निकेतन, नवादा की बस बीआर 27 ई-2883 पर ओवर पैसेंजर मामले में 2,000 का फाइन किया गया। इसी तरह गुरु द्रोणाचार्य पचिलक स्कूल की बस बीआर 27पी-1903 पर अतिरिक्त सवारी बैठाने के आरोप में 2,000 का जुर्माना लगाया गया। चंद्रा ओपन माइंड स्कूल की बस बीआर 27पी-1202 पर फिटनेस, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने पर 9,000 का चालान हुआ। वहीं रेजिडेंशियल जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल की बस बीआर 27सी-2385 पर फिटनेस, इंश्योरेंस, प्रदूषण और ओवरलोडिंग के मामले में 9,800 का जुर्माना लगाया गया।

वाहन की जांच करती पुलिस पदाधिकारी

अभिनंदन महाबोधि मंदिर में की पूजा-अर्चना, बौद्ध परंपरा के प्रति जताई गहरी आस्था

वियतनाम के राष्ट्रपति का गयाजी में सीएम ने किया स्वागत

AGENCY GAYAJI: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम मंगलवार को ज्ञान और मोक्ष की भूमि गयाजी पहुंचे। बोधगया अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति तो लाम 5 से 7 मई तक भारत दौरे पर हैं। गयाजी एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रोटोकॉल के तहत उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संक्षिप्त लेकिन सौहार्दपूर्ण बातचीत भी हुई। स्वागत समारोह में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का अभिनंदन किया और उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया।

एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सड़क मार्ग से महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति ने कुछ समय ध्यान भी किया और बौद्ध परंपराओं के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। उनके साथ वियतनाम का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा।

बोधगया के हवाई अड्डे पर विमान से उतरते वियतनाम के राष्ट्रपति व पुष्पगुच्छ भेंट करते सीएम सम्राट चौधरी

राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर गयाजी जिला प्रशासन कई दिनों से तैयारी में जुटा हुआ था। एयरपोर्ट से लेकर महाबोधि मंदिर तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जगह-जगह पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई थी। मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की सघन जांच की गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी गयाजी में राष्ट्रपति का आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह भारत-वियतनाम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रपति बोधगया के अन्य प्रमुख बौद्ध स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए शहर में साफ-सफाई, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन को दुरुस्त किया गया है, साथ ही विदेशी प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं।

सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का कल होगा विस्तार, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह

AGENCY PATNA : बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस बहुप्रतीक्षित विस्तार को लेकर आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार को जानकारी दी कि 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें कई बड़े राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति तय मानी जा रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नए मंत्रियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं। वहां एक भव्य मंच का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही विशिष्ट अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के लिए बैठने की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर विस्तृत योजना बनाई जा रही है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ली थी। तभी से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थीं, जो अब 7 मई को खत्म होने जा रही हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

उद्योग जगत की खुशी बंगाल के फिर से निवेश और नौकरियों का केंद्र बनने का संकेत है

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का असर बाजार में भी तुरंत दिखाई दिया। सेंसेक्स में अच्छी बढ़त दर्ज की गई और कोलकाता की कई कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक स्थिर और स्पष्ट नीतियों को प्राथमिकता देते हैं।

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम केवल राजनीतिक बदलाव ही नहीं लाये बल्कि राज्य के आर्थिक भविष्य को लेकर नई उम्मीदें भी जगाई हैं। उद्योगपति हर्ष गोयनका की प्रतिक्रिया ने इस चर्चा को और गति दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल का व्यापारिक वर्ग इस परिणाम से खुश है और अब विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की यह जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार उसने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के पंद्रह साल के शासन का अंत हुआ है। इस बदलाव से केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद की जा रही है, जो विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का असर बाजार में भी तुरंत दिखाई दिया। सेंसेक्स में अच्छी बढ़त दर्ज की गई और कोलकाता की कई कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक स्थिर और स्पष्ट नीतियों को प्राथमिकता देते हैं। जब राज्य और केंद्र की सरकारें एक दिशा में काम करती हैं, तो निवेश का माहौल बेहतर बनता है। हालांकि, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि बाजार की यह तेजी शुरूआती प्रतिक्रिया हो सकती है। दीर्घकाल में आर्थिक स्थिति कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की कीमतें।

उद्योग जगत को उम्मीद है कि अब बड़े आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। निवेश की मंजूरी की प्रक्रिया आसान हो सकती है और नियमों में स्पष्टता आएगी। इससे निजी और सरकारी दोनों तरह के निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का विस्तार भी राज्य में तेजी से हो सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय और मांग बढ़ने की संभावना है। कई उद्योग संगठनों ने भी इस परिणाम का स्वागत करते हुए निवेश के माहौल में सुधार की उम्मीद जताई है।

अगर विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, तो आधारभूत ढांचा और निर्माण क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। सड़क, बंदरगाह और औद्योगिक परियोजनाओं को गति मिल सकती है। अचल संपत्ति क्षेत्र में भी सुधार की उम्मीद है। चाय, कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में नई योजनाएं विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कर्ज वितरण बढ़ सकता है, खासकर छोटे उद्योगों और आवास क्षेत्र में।

इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से दबाव में है। वित्तीय घाटा और कर्ज का स्तर ऊंचा बना हुआ है। ऐसे में नई सरकार के लिए अपने वादों को संतुलित तरीके से लागू करना जरूरी होगा, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल राजनीतिक बदलाव पर्याप्त नहीं है। नीतियों का सही क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन ही लंबे समय में वास्तविक परिणाम तय करेंगे। वैसे आम लोगों के लिए इस बदलाव का अर्थ है संभावित रूप से अधिक रोजगार के अवसर और बेहतर आर्थिक गतिविधियां। अगर निवेश बढ़ता है और उद्योग विकसित होते हैं, तो राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। इससे जीवन स्तर और बाजार की स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल अभी भी निवेश के मामले में अन्य राज्यों से पीछे है। विदेशी निवेश कम रहा है और विनिर्माण क्षेत्र की गति भी धीमी रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवाओं का योगदान अधिक है, जबकि औद्योगिक विकास को और मजबूत करने की जरूरत है। व्यापार करने की सुविधा से जुड़े पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। जमीन की उपलब्धता, मंजूरी की प्रक्रिया और नियमों की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सुधार जरूरी है।

हम आपको याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल का औद्योगिक इतिहास कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। एक समय ऐसा था जब यह राज्य अपने कारखानों और उद्योगों के कारण पूरे देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में पहचान रखता था। दूसरे राज्यों से लोग यहां रोजगार की तलाश में आते थे। लेकिन समय के साथ स्थिति बदलती चली गई। पहले वामपंथी सरकारों की नीतियों के कारण उद्योगों पर दबाव बढ़ा और धीरे धीरे कई कारखाने बंद होने लगे। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार और नीतिगत अनिश्चितता को लेकर भी सवाल उठते रहे, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। ममता बनर्जी के आंदोलन के चलते सिंगूर में टाटा नैनो परियोजना के बंद होने की घटना के बाद बंगाल में बड़े उद्योग लगाने को लेकर निवेशकों में एक तरह की हिचक पैदा हो गई। परिणाम यह हुआ कि रोजगार के अवसर घटे और लोगों का पलायन बढ़ने लगा। हालांकि अब जब भाजपा की सरकार बनी है, तो उद्योग जगत में एक बार फिर सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई उद्योग संगठनों का कहना है कि वह आने वाले समय में सरकार को नई परियोजनाओं की रूपरेखा सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को फिर से गति मिल सकती है।

बहरहाल, पश्चिम बंगाल एक नए अवसर के दौर में प्रवेश कर रहा है। अगर नई सरकार योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करती है और निवेश के अनुकूल माहौल बनाती है, तो राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकती है।

संपादकीय

दक्षता घटाती कोचिंग

पिछले दिनों आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर प्रो. सुमन चक्रवर्ती के उस बयान ने चौंकाया कि कोचिंग के कारोबार ने छात्रों की सोचने की क्षमता को घटाया है। वे प्रतिभा विस्तार व मौलिक सोच में विकास के बजाय कोचिंग उद्योग के चतुराई के खेल में शामिल हो रहे हैं। वे दिमाग के इस्तेमाल के बजाय जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए ट्रिक्स से गलत ऑप्शन हटाना सीख रहे हैं। फलतः वे आईआईटी जैसे उच्च संस्थानों में प्रवेश तो पा जाते हैं, लेकिन गुणवत्ता की शिक्षा से साम्य बैठाने में असफल साबित होते हैं, जिससे उनकी आईआईटी में बैक लगने यानी कुछ विषयों अनुतीर्ण होने से बैक लगने की स्थिति पैदा हो रही है। जिससे वे अक्सर तनाव में आ जाते हैं। हो सकता आने वाले समय में किसी अध्ययन व शोध से यह बात सामने आए कि उच्च तकनीक संस्थानों में बढ़ती आत्मघात की प्रवत्ति के पीछे कोचिंग संस्थानों की भेड़चाल से उपजी विसंगतियां हों। निश्चय ही यह स्थिति भारतीय उच्च व तकनीकी संस्थानों में विकसित हो रही इस नकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली है। एक समय था कि भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रणाली में स्वस्थ स्पर्धा हुआ करती थी। प्रतिभावान विद्यार्थी ही उच्च तकनीकी संस्थानों में प्रवेश पा सकते थे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बाजार के लगातार बढ़ते दखल ने सारी स्थिति ही उलट कर रख दी। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्डों द्वारा सौ फीसदी तक अंक दिए जाने ने राज्यों के बोर्डों से परीक्षा उतीर्ण करने वाले छात्रों को हीन भावना से भर दिया। निस्संदेहद, वह शिक्षा प्रणाली सवालों के दायरे में आनी चाहिए, जिसमें असंभव से लगने वाले सौ फीसदी अंक छात्रों को दिए जाते हैं। सौ फीसदी अंक एक नहीं कई-कई छात्रों को दिए जाते हैं। वहीं राज्यों के विभिन्न बोर्डों में परीक्षक कंजूसी से नंबर देकर पहले ही छात्रों को राष्ट्रीय स्पर्धा से बाहर कर देते हैं। निश्चय ही यह स्थिति देश के लाखों छात्रों के साथ अन्याय जैसी है।

दरअसल, देश में पहले भी कोचिंग व्यवस्था मौजूद रही है। लेकिन एक सहायक की भूमिका में। आज कोचिंग कारोबारियों द्वारा उसे छात्रों के भविष्य का निर्धारण करने वाले एकमात्र विकल्प के रूप में बताया जा रहा है। यह व्यवस्था देश में व्याप्त आर्थिक विभेद को भी और बढ़ाती है। तय है कि संपन्न घरों से आने वाले बच्चे महंगी कोचिंग पाकर गुदड़ी के लालों के जीवन पर सदैव भारी पड़ेंगे। फलतः कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों के अभिभावक बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कर्ज लेकर कोचिंग का जुगाड़ करते हैं। अपना पेट काटकर वे बच्चों को महंगे कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं। कई अभिभावक अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। वहीं शैक्षिक गुणवत्ता के नजरिये से देखें तो पहले जब कोचिंग एक सहायक की भूमिका में थी तो छात्र विस्तृत पढ़ाई से विषय को समझने का प्रयास करते थे। अब पूरी व्यवस्था कोचिंग केंद्रित होने से शिक्षा की व्यापकता खत्म हो रही है। इसका नकारात्मक प्रभाव यह है कि छात्र परीक्षा के तीन घंटों में सवाल समझकर हल करने की बजाय गलत विकल्पों को हटाने की कोचिंग्स द्वारा सिखायी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। दरअसल, कोचिंग संस्थानों के तौर-तरीकों से छात्रों को ह्यस्पून फीडिंगह्न की लत लग जाती है। वहां हिंदी में पढ़ाई होती है और तैयार नोट्स को बार-बार रटाया जाता है। वहीं विडंबना यह है कि आईआईटी आदि उच्च तकनीकी संस्थानों में पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। वहां समेस्टर सिस्टम में पढ़ाई सेल्फ-स्टडी पर आधारित होती है। यही वजह है कि महज ट्रिक्स द्वारा आईआईटी में प्रवेश करने वाले छात्र आगे की पढ़ाई के साथ साम्य नहीं बैठा पाते। उनको कई विषयों में पूरक परीक्षा देनी पड़ती है, जिससे सुनहरे सपने लेकर आए छात्र गहरे तनाव में आ जाते हैं।

चिंतन-मनन

नफरत का बोझ

बहुत पुरानी कथा है। एक बार एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों से अनुरोध किया कि वे कल प्रवचन में आते समय अपने साथ एक थैली में बड़े-बड़े आलू साथ लेकर आएं। उन आलुओं पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए, जिससे वे नफरत करते हैं। जो शिष्य जितने व्यक्तियों से घृणा करता है, वह उतने आलू लेकर आए। अगले दिन सभी शिष्य आलू लेकर आए। किसी के पास चार आलू थे तो किसी के पास छह। गुरु ने कहा कि अगले सात दिनों तक ये आलू वे अपने साथ रखें। जहां भी जाएं, खाते-पीते, सोते-जागते, ये आलू सदैव साथ रहने चाहिए। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वे क्या करते, गुरु का आदेश था। दो-चार दिनों के बाद ही शिष्य आलुओं की बदबू से परेशान हो गए।

जैसे-तैसे उन्होंने सात दिन बिताए और गुरु के पास पहुंचे। सबने बताया कि वे उन सड़े आलुओं से परेशान हो गए हैं। गुरु ने कहा- यह सब मैंने आपको शिक्षा देने के लिए किया था। जब सात दिनों में आपको ये आलू बोझ लगने लगे, तब सोचिए कि आप जिन व्यक्तियों से नफरत करते हैं, उनका कितना बोझ आपके मन पर रहता होगा। यह नफरत आपके मन पर अनावश्यक बोझ डालती है, जिसके कारण आपके मन में भी बदबू भर जाती है, ठीक इन आलुओं की तरह। इसलिए अपने मन से गलत भावनाओं को निकाल दो, यदि किसी से प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम नफरत तो मत करो। इससे आपका मन स्वच्छ और हल्का रहेगा। सभी शिष्यों ने वैसा ही किया।

क्या भारत दो-दलीय राजनीति की ओर बढ़ रहा है?

दिलीप कुमार पाठक

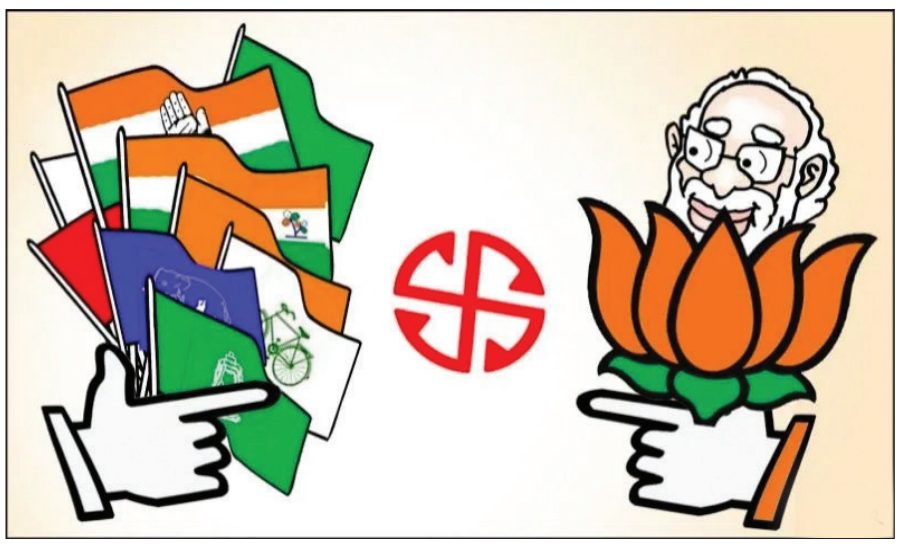

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐसी बात निकलकर आई है, जिसे समझना जरूरी हो गया है। कभी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाली भाजपा का ये सियासी जुमला लगता था, लेकिन आज की हकीकत देखें तो यह क्षेत्रीय दल मुक्त भारत के एक बड़े प्लान की तरह नजर आता है। भाजपा की रणनीति अब स्पष्ट हो चली है, वह पहले बड़े प्यार से किसी क्षेत्रीय दल की 'बांह' पकड़ती है, उसके साथ मिलकर सरकार बनाती है, वहाँ का गुणा गणित समझती है, उसके घर के भीतर तक अपनी पैठ बनाती है और फिर धीरे से उसी साथी को किनारे लगाकर अपना झंडा गाड़ देती है।

नीतीश कुमार हों या उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक हों या बादल परिवार... इन सब की कहानियाँ एक ही पैटर्न पर लिखी गई हैं। बिहार को ही देख लीजिए, जहाँ नीतीश कुमार कभी बड़े भाई हुआ करते थे और भाजपा उनके पीछे चला करती थी। लेकिन आज पासा पूरी तरह पलट चुका है; भाजपा बिहार की सबसे बड़ी ताकत बन गई है और नीतीश अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस शिवसेना ने भाजपा को उंगली पकड़कर हिंदुत्व का रास्ता दिखाया, आज वह खुद दो टुकड़ों में बंटकर अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही है। ओडिशा में नवीन बाबू का 24 साल पुराना अभेद्य किला जिस तरह ढहा, उसने सबको हैरान कर दिया। भाजपा ने वहां पहली बार अपनी सरकार बनाकर साबित कर दिया कि वह किसी की भी विरासत को समेटने का हुनर जानती है। अभी एक दशक पहले बंगाल में भाजपा का अस्तित्व भी न के बराबर था, लेकिन आज वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ ही साथ सरकार बन गई है।

अब यह विस्तार की भूख पंजाब और दक्षिण के राज्यों की ओर मुड़ चुकी है। पंजाब में अकालियों से नाता टूटने के बाद भाजपा ने जो ताकत दिखाई है, वह आने वाले समय में केजरीवाल की आप के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। दक्षिण भारत अब भाजपा के लिए एक ऐसी प्रयोगशाला बन गया है जहाँ वह नए-नए प्रयोग कर रही है। तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से दो ही नाम चलते थे–डीएमके और एआईएडीएमके लेकिन भाजपा ने एआईडीएमके के कमजोर पड़ते ही वहां अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। केरल में जहाँ कांग्रेस और वामपंथियों के अलावा किसी तीसरे की जगह नहीं थी, वहाँ भाजपा ने त्रिशूर की सीट जीतकर और अपना वोट शेयर बढ़ाकर सबको चौंका दिया है। कांग्रेस वहां आज भले ही जीत गई हो, लेकिन उसे भी पता है कि भाजपा की नजरें अब उसकी कुर्सी पर हैं।

बंगाल जीतने के बाद पार्टी मुख्यालय के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का विरोध करना अखिलेश यादव को बहुत भारी पड़ेगा, मतलब साफ है अगला नंबर उत्तरप्रदेश का है। भाजपा जिस आत्मविश्वास के साथ अखिलेश यादव को टार्गेट कर रही है, और जैसे परिणाम आ रहे हैं तो लगता है कि भाजपा यूपी को जीतकर समाजवादी पार्टी को भी नफासत के साथ निपटा देगी।

भाजपा अब उन मुद्दों को पीछे धकेल रही है जिन मुद्दों के सहारे क्षेत्रीय दलों की रणनीतिक अस्तित्व टिका हुआ है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस का अपना अलग ही तर्क है। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा की इस आक्रामक विचारधारा का मुकाबला नहीं कर सकतीं। वे कहते हैं कि अंत में मुकाबला बड़ा होगा और देश फिर से कांग्रेस बनाम भाजपा वाले दौर में लौटेगा। यानी कांग्रेस भी चाहती है कि क्षेत्रीय दल कमजोर हों ताकि वह मुख्य विपक्षी दल बन सके। थलापति विजय जैसे नए चेहरे तमिलनाडु में उम्मीद तो जगाते हैं, लेकिन इसके बाद वहाँ भाजपा जिस स्टाइल में काम कर रही है, उसमें किसी तीसरे के लिए रास्ता बनाना आसान नहीं होगा।

सवाल यह है कि क्या यह सब लोकतंत्र के लिए सही है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कुछ कोस पर भाषा और संस्कृति बदल जाती है। क्षेत्रीय दल इन्हीं स्थानीय भावनाओं की आवाज होते हैं। अगर ये दल खत्म हो गए, तो क्या स्थानीय मुद्दे दिल्ली के शोर में दब जाएंगे? भाजपा अब किसी राज्य में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहने से संतुष्ट नहीं होती। वह जहां कदम रखती है, पूरा मैदान अपना करने की कोशिश करती है। आने वाले समय में अगर ये क्षेत्रीय क्षत्रप नहीं संभले, तो देश में सिर्फ दो बड़े ध्रुव ही बचेंगे? ये तो समय बताएगा, हालांकि अब यह जनता को तय करना है कि क्या उन्हें वह एक छत्र राज मंजूर है या वे अपनी स्थानीय पहचान और आवाज को बचाए रखना चाहते हैं।

(लेखक पत्रकार हैं)

किराये की संतान नहीं, अपनत्व का पुनर्जागरण चाहिए

ललित गर्ग

जीवन की सांझ जब अपने पूरे विस्तार के साथ उतरती है, तब मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता दवाइयों या धन की नहीं, बल्कि अपनों के सान्निध्य और अपनों की होती है। यह वही समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन की संचित स्मृतियों, अनुभवों और भावनाओं को साझा करना चाहता है। लेकिन आज का कठोर यथार्थ यह है कि अनेक बुजुर्ग अपने ही घरों में अजनबी-से होकर रह गए हैं। विशाल मकानों में गूंजती खामोशी, सूने आंगन, और दरवाजे पर टकटकी लगाए प्रतीक्षा करती आंखें-यह सब मिलकर एक ऐसी त्रासदी रचते हैं, जो केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक विघटन का संकेत है। आज वैश्वीकरण, रोजगार की अनिवार्यता और बेहतर भविष्य की तलाश ने नई पीढ़ी को देश-विदेश के कोनों में बिखेर दिया है। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी कीमत चुकाई जा रही है, वह है पारिवारिक संवेदना का क्षरण। अनेक बच्चे विदेश जाकर वहीं बस जाते हैं, अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि माता-पिता केवल फोन कॉल और औपचारिक संदेशों तक सीमित रह जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो एक ही शहर में रहते हुए वर्षों तक माता-पिता की सुध नहीं लेते। यह केवल दूरी की समस्या नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी का संकट है।

इसी संवेदनहीनता के वातावरण में एक नया और विचलित करने वाला प्रचलन उभरा है-'किराये की संतान'। कुछ कंपनियां और संस्थान अब ऐसे युवाओं या बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं, जो बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ सैर करते हैं, खेलते हैं और उनके अकेलेपन को कुछ हद तक कम करने का प्रयास करते हैं। पहली दृष्टि में यह व्यवस्था राहत देती प्रतीत होती है, लेकिन गहराई से देखने पर यह हमारे सामाजिक ढांचे की विफलता का प्रमाण बन जाती है। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है-क्या अब ममता और अपनत्व भी अनुबंधों और पैकेजों में बांटे जाएंगे? क्या संबंधों की गरमाहट अब सेवा-शुल्क के साथ उपलब्ध होगी? यह स्थिति केवल विडंबना नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक चेतावनी है कि हम अपने मूल्यों से कितनी दूर चले आए हैं। किराये की संतान सुलभ कराने की परम्परा आधुनिक समाज-संरचना की एक बड़ी विडम्बना एवं त्रासदी है।

हालांकि यह भी सत्य है कि हर परिवार की परिस्थितियां समान नहीं होतीं। कई बार बच्चों के सामने ऐसी मजबूरियां होती हैं, जिनके कारण वे माता-पिता के साथ नहीं रह पाते। वहीं कुछ बुजुर्ग भी अपने स्वभाव या सोच के कारण नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। लेकिन इन अपवादों के बावजूद, व्यापक स्तर पर जो प्रवृत्ति उभर रही है, वह आत्मकेंद्रित जीवनशैली और संवेदनाओं के ह्रास की ही परिणति है। और भी चिंताजनक तथ्य यह है कि यह सुविधा केवल उन बुजुर्गों के लिए सुलभ है, जिनके पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन हैं। मध्यमवर्गीय या निम्नवर्गीय बुजुर्ग, जिनकी आय के स्रोत सीमित हो चुके हैं, वे इस प्रकार की सेवाओं का खर्च वहन नहीं कर सकते। निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है, जहां पेंशन नगण्य होती है और चिकित्सा खर्च लगातार बढ़ते जाते हैं। ऐसे में उनका जीवन आर्थिक असुरक्षा और मानसिक अवसाद के बीच झूलता रहता है।

निश्चिततौर पर आज का समाज तीव्र गति से बाजारवाद और भौतिकवाद की ओर बढ़ रहा है, जहाँ संबंधों की ऊष्मा और भावनाओं की गहराई धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है। जीवन की प्राथमिकताएँ अब मानवीय मूल्यों से हटकर उपभोग, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक सफलता तक सीमित हो गई हैं। परिणामस्वरूप रिश्ते भी उपयोगिता और स्वार्थ के आधार पर आँके जाने लगे हैं। परिवार, जो कभी संवेदना, सहारा और संस्कार का केंद्र हुआ करता था, अब व्यस्तताओं और महत्वाकांक्षाओं के दबाव में बिखरता नजर आ रहा है। इस बदलते परिवेश में बुजुर्ग पीढ़ी सबसे अधिक उपेक्षित हो रही है, क्योंकि वे न तो बाजार की दौड़ में शामिल हो सकते हैं और न ही नई पीढ़ी की भौतिक अपेक्षाओं को पूरा कर पाते हैं। उनके अनुभव, त्याग और स्नेह को अब बोझ या बाधा के रूप में देखा जाने लगा है। संयुक्त परिवारों के टूटने और एकल परिवारों के बढ़ने से उनकी सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा भी कमजोर हुई है। डिजिटल दुनिया ने संवाद को और अधिक सतही बना दिया है, जिससे आत्मीयता का स्थान औपचारिकता ने ले लिया है। ऐसे में बुजुर्गों का अकेलापन, असुरक्षा और उपेक्षा बढ़ती जा रही है, जो हमारे समाज के नैतिक पतन का संकेत है।

विकसित देशों में बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मजबूत व्यवस्थाएं हैं। वहां सरकारें उनकी स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन और देखभाल की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसके विपरीत भारत में, जहां परिवार को ही सबसे बड़ी सुरक्षा माना गया था, आज वही ढांचा कमजोर पड़ता जा रहा है। सरकारें कर तो वसूलती हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए समुचित कल्याणकारी योजनाओं का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसी परिस्थितियों में समाधान केवल भावनात्मक अपील तक सीमित नहीं रह सकता। इसके लिए बहुआयामी और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें पारिवारिक मूल्यों के पुनर्जागरण की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। बच्चों में बचपन से ही माता-पिता के प्रति कर्तव्यबोध, सम्मान और संवेदना का संस्कार विकसित करना होगा। शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम न होकर, जीवन मूल्यों का संवाहक बनेकृयह सुनिश्चित करना समय की मांग है।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम है-वृद्धाश्रमों और अनाथालयों का एकीकरण। यह विचार केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक अत्यंत व्यावहारिक और मानवीय समाधान हो सकता है। यदि एक ही परिसर में बुजुर्गों और अनाथ बच्चों को साथ रखा जाए, तो दोनों की समस्याओं का समाधान संभव है। बच्चों को जहां स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं बुजुर्गों को अपनत्व और बच्चों के साथ का अनुभव होगा। यह संबंध कृत्रिम नहीं, बल्कि स्वाभाविक और आत्मीय होगा। सरकार को इस दिशा में नीतिगत पहल करनी चाहिए। सुविधा-संपन्न, गरिमामय और मानवीय वृद्धाश्रमों का निर्माण, जहां केवल देखभाल ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी समावेश हो, यह अत्यंत आवश्यक है। साथ ही निजी संस्थाओं को भी इस क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करते हुए कि सेवाएं केवल व्यवसाय न बन जाएं, बल्कि सेवा का भाव प्रमुख रहे। बुजुर्गों को भी इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि जीवन का यह चरण आत्मनिर्भरता और आत्मबल की मांग करता है। योग, ध्यान, प्राणायाम, सत्संग और सामाजिक सहभागिता उनके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। डिजिटल साक्षरता भी उन्हें अपने बच्चों और समाज से जुड़े रहने में सहायक हो सकती है।

साररूप में यह समझना होगा कि समाज केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि संवेदनाओं की समृद्धि से विकसित होता है। यदि हम अपने बुजुर्गों को सम्मान, स्नेह और सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारी सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। 'किराये की संतान' का प्रचलन हमें यह सोचने पर विवश करता है कि कहीं हम संबंधों को भी वस्तु तो नहीं बना रहे, भौतिकता की तराजू में तो नहीं तौल रहे हैं। यह समय है आत्ममंथन का अपने भीतर झांकने का और यह तय करने का कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। यदि हम सच में एक स्वस्थ, संवेदनशील और संतुलित समाज की कल्पना करते हैं, तो हमें अपनत्व के उस दीप को पुनः प्रज्वलित करना होगा, जिसकी रोशनी में हर बुजुर्ग अपने जीवन की सांझ को गरिमा और सुकून के साथ जी सके।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Vijay's secular win eases BJP's southern push

AS in his countless films, Vijay has emerged as the victorious hero, this time in his electoral debut, vanquishing his rivals. Vijay's party, the Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), has decisively trounced the ruling DMK-led Secular Progressive Alliance and the AIADMK-led National Democratic Alliance.The Vijay wave did not spare even Chief Minister MK Stalin. He lost in Kolathur, from where he was elected hands down in the previous three elections, to a former DMK worker who joined the TVK earlier this year after being sidelined by the DMK.Powered by votes from the young, women, minorities and Dalits, and the strong anti-incumbency against the DMK government of Stalin, Vijay's historic victory has all the makings of the kind of political shift that Tamil Nadu has seen only twice before: in the defeat of the Congress by the DMK in 1967, and of the DMK by the breakaway MG Ramachandran-led AIADMK in 1977. Unlike the AIADMK that had a pre-election alliance with Left parties, the TVK went solo in this election.

The Tamilaga Vettri Kazhagam, a two-year-old outfit, is poised to win about 107 seats, with 118 required for a majority. The DMK, which in 2021 won 133 seats on its own and 159 along with its SPA partners, was trailing far behind with some 70-plus seats, with the AIADMK at the third place. Other DMK bigwigs, including several ministers, were felled across the state.

The DMK wunderkid, Palanivel Thiaga Rajan, has also lost. His constituency houses the famous Madurai Meenakshi temple and was being eyed for its potential for communal polarisation, particularly as it is next to Thiruparankundram, where an old land row between the managements of a temple and a dargah has created communal disturbances in recent months.The saffron party fielded C Sundar, husband of actor Khushboo, the party's Tamil Nadu unit vice-president. But in an ironic twist, the winner is Madhar Badrudeen, a Muslim candidate and a newcomer to politics, put up by the TVK, a party whose secular credentials are a silver lining of this election in which people voted for "change" without knowing what Vijay intends to change and how.

Despite the mega shift away from the two Dravidian parties, the likelihood of a hung Assembly remains high. The TVK's tally is short of the majority mark despite coming tantalisingly close to the magic number of 118 in the 234-seat Tamil Nadu Assembly. The Congress could be a natural partner.

Vijay, whose full name is C Joseph Vijay, is a Christian. In recent times, he has visited churches, mosques and temples, seeking to consolidate various religious communities behind him. He has also broken away a significant chunk of Dalit votes from the traditional representatives of the community, such as the Viduthalai Chirthaikal Katchi.

The Congress had reached out to him before the election, but abandoned the effort mid-way. The Pattali Makkal Katchi, which is now led by Anbumani Ramadoss, son of the founder, Dr S Ramadoss, is also a candidate, as it has no big differences with the TVK. A hung Assembly has always been a happy hunting ground for the BJP; so no party should be counted out.

In a state where the ruling party gets voted out every five years, the DMK believed it would be able to repeat what Jayalalithaa had pulled off in 2016 by leading the AIADMK to a second successive win. The DMK thought it could achieve this by side-stepping anti-incumbency and framing this election as a battle to keep intact India's federalism against the BJP's centralising tendencies and as a battle against Hindutva.Tschemes. Such schemes are now taken for granted by the Tamil Nadu voter.

India must look beyond UAE's OPEC exit

Remember that Abu Dhabi doesn't make its energy policies to suit India

THE exit of the United Arab Emirates (UAE) from the Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) has a long and chequered history. It renders the rejoicing in India over Abu Dhabi's decision premature and simplistic. Abu Dhabi joined OPEC as an individual emirate in 1967 and continued as a member after the UAE was formed in 1971. The UAE seldom stuck to its OPEC production ceiling from the early years of its membership of the cartel.Unlike today, Dubai was not a tourism destination in the 1970s and oil produced by the Dubai Petroleum Company was an important source of income for the emirate. Dubai sold most of its oil in the spot market and refused to adhere to OPEC quotas imposed on the UAE. The nascent federation was not strong enough then to enforce its collective will on constituent emirates.

Therefore, it is important for those who make India's oil policy to note that within OPEC — or now outside it — the UAE's membership has seldom made much difference to the cartel. Rankings, production percentages and similar parameters are irrelevant in this context. That is why India's notion that OPEC will be crippled because of last week's UAE decision to quit the organisation is not founded in fact.

In 1982, when Mana Saeed Al Otaiba, the UAE's first Minister for Petroleum and Mineral Resources, returned home from Vienna after presiding over the 63rd OPEC Ministerial Conference, he called this writer and two other Dubai-based journalists for a conversation. When we asked about the meeting, he made a shrug-like gesture with both palms open upward, indicating that if the conference had any outcome, he did not comprehend it.He then took out two sheets of the OPEC note paper, which had doodles on both pages. Otaiba, who was a prolific poet even before he became a minister at the age of 25, was known to doodle or write poetry during the OPEC meetings to idle away his time in attendance. Otaiba has to his credit a vast repertoire of poetry, fiction and scholarly books on Arabia's petroleum industry.A year later, returning from the London OPEC Ministerial Conference, Otaiba showed us, the same three journalists, a poem he had written during that long meeting. The poem, in part, read as follows:

"I am truly troubled,
And with OPEC distressed,
OPEC's crisis no longer suppressed,
The market is stagnant,
The price of crude oil depressed.
We called for a London meeting
As the market was explosive,
The solution must be comprehensive,
Strength is now imperative,
Let production have a ceiling,
Since luck is surely offensive."

These anecdotes are important now because Otaiba's doodling and poetry reflected disdain for OPEC. Oil industry historians will aver that the UAE nearly quit the cartel on several occasions.

The path for OPEC was never smooth. It faced bitter break-ups many times. In the first five months of 1986, OPEC held four contentious ministerial meetings to discuss production ceilings for its members. In the preceding 12 months, OPEC ministers met eight times. Otaiba walked out of at least one of these meetings in Geneva. According to records maintained by the US government's Energy Information Administration, OPEC's disagreements pushed down oil prices to $9.25 a barrel that year from a high of $24.51 in 1985.

But OPEC did not fold up. There is no reason to believe that the UAE's departure will be a fatal blow for the cartel. And it is unreasonable to expect that unless a day dawns when viable alternatives to oil are in currency, crude prices will ever again go down to $9.25 because OPEC is at war with itself.

Last week, in the evolving global energy scenario, India appeared to be setting much store by its close friendship with the UAE. Public discourse must dispel any impression that Abu Dhabi makes its energy policies to suit India. It crafts policies that are meant to protect its vital interests. Everything else is secondary.

There is also insfficient understanding in India that Abu Dhabi's energy organisation sector is not a monolith. It has not been since the mid-1970s, when the Ministry for Petroleum and the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) were separated. The ADNOC became responsible for oil and gas operations while the ministry decided oil policies.

In a rare interview in the 1980s, Mahmoud Hamra Krouha, a self-effacing Algerian who set up the ADNOC and was its first General Manager, told me that his mission was to double Abu Dhabi's oil production through new drilling. This did not exactly square with the thinking within the ministry, which worried about overcapacity.

The bifurcation exists to this day. Krouha's successor now is technocrat Sultan Al Jaber, who has the dual titles of Group CEO and Managing Director of the ADNOC. India engages with Al Jaber regularly, but it is imperative that India should be clear about what it now wants from the UAE in the context of its post-OPEC energy policies.

What are the emerging contours of these policies? Until the ongoing military standoff between the US and Iran ends and solutions to sticking points between them are found, the UAE's goodbye to OPEC will not make an iota of difference to energy-consuming countries like India. How long that will take is anyone's guess.

Hardly any crude passes through the Strait of Hormuz now because of the standoff. The only outlet for the UAE's oil exports now is through its constituent emirate of Fujairah that bypasses the Strait of Hormuz. But the pipeline to Fujairah port can handle only 1.8 million barrels per day. How much of this volume will the UAE export to India, which is only one of its global customers? Has India factored this critical limitation into its calculations about the UAE?Ultimately, the Emiratis and Saudis are "brothers" while the Indians, Chinese or Japanese are their "friends." Despite brotherly bickering, the UAE and Saudi Arabia are conjoined twins. Their latest annual non-oil trade totalled $41.3 billion, according to UAE government figures.The UAE is the second biggest foreign direct investor in the kingdom while Saudi investments in the UAE are worth $4.3 billion. Like a sudden boycott of Qatar by three Gulf countries ended unexpectedly, the UAE-Saudi rift will also heal at some point. India must bear that in mind while making its policies.

Alert India: Quick response across states a challenge

Early warning is only the first link in the chain. Its value depends on what follows

INDIA's emergency architecture is entering a new phase. The "Extremely Severe Alert" that rang out across millions of phones on Saturday during a nationwide test by the National Disaster Management Authority and the Department of Telecommunications was more than a technological trial. Using cell broadcast, messages can be pushed simultaneously to all devices in a defined area, bypassing congested networks and even silent modes. In disaster scenarios, that capability can mean the difference between timely evacuation and chaos.But early warning is only the first link in the chain. Its value depends on what follows. Here, the performance of the Himachal Pradesh Police under the 112 Emergency Response Support System is instructive. With an average response time of about three minutes 36 seconds and minimal dispatch delays, it shows how integrated control rooms, GPS-enabled patrols and streamlined call handling can translate alerts into action. Such efficiency is particularly critical in terrains like Himachal's, where geography often slows intervention. The broader lesson is about integration. India now has the building blocks of a modern emergency grid: a unified helpline (112), real-time alert capability and improved data-driven policing. Yet, these systems do not operate uniformly. Response times in many states remain significantly higher, reflecting disparities in manpower, training and infrastructure.Equally pressing is the communication gap. The recent alert triggered confusion because citizens were not adequately informed about test protocols or alert categories. Trust in such systems depends as much on public awareness as on technological reliability. The way forward lies in convergence and consistency. Standardising response benchmarks, investing in local capacity and institutionalising public outreach can turn scattered gains into a nationwide safety net. The test alert was a warning bell. It was more about preparedness.

Time to revisit anti-defection law

Defectors must lose their seats even if the breakaway entity qualifies to be recognised as a separate party

THE "transmogrification" of seven Rajya Sabha MPs (Members of Parliament) of the Aam Aadmi Party has reignited the defection debate. While this phenomenon might not be unique to India, it seems a form of "soul-searching" by people increasingly accused of not possessing one. It represents the art of being here today and there tomorrow with the craft of doing it with guile and without guilt.Changing one's political beliefs and affiliation should normally be treated as a process of "growing up" politically due to a change of heart or ideological awakening. Elected representatives are 'jolted' by their conscience, smitten by a realisation of their leader's "betrayal", and a desire for betrothal with another party they decried. Elegy and eulogy merge into something hard to define and difficult to understand.

The Constitution guarantees liberty of thought and expression and the right to form associations. Then, why label this "defection" a negative political behaviour necessitating a law to regulate such conduct? The Constitution didn't deal with defection originally in its innocent belief in the strength of character of the political class.I won't venture into the history of defections in India, although I served the state credited with the origin of the species of Aaya Ram, Gaya Ram. Haryana gave a live demonstration of the Bhagavad Gita sermon of the soul never dying but changing form, when the chief minister led his cabinet to mutate by joining another party in 1980.What bears elaboration, however, is while defection is undesirable, to act as per free will is fundamental to the concept of freedom. Many see the Tenth Schedule of the Constitution, introduced by the 52nd Amendment Act (1985), and its subsequent modification by the 91st Amendment Act (2003) as a deterrent to elected representatives acting of their free will. The anti-defection law was brought about to ensure political stability by disallowing the UK-style 'free-seating' in Parliament. However, this merely dissuaded solitary acts of changing political loyalties but allowed wholesale transaction, originally one-third, increased later to two-thirds of the party inside and outside the House.The utilisation in politics of the effective trade practice of "bulk-buying" reflects both a time-tested market formula and a morally resilient political culture. In politics, bulk discount converts into a premium because those who put themselves on offer must ensure being bundled with kindred souls in order to make up the two-thirds. The unique feature of this product is that only two-thirds of the whole is sold; one-third is retained for a possible resale, should circumstances so warrant. The circumstances could be created by the "inner voice" that scriptures exhort us to hear or the scripted "external threat" that the mind is trained to perceive.

Legal luminaries will now delve into the nuances of law and the litany of relevant judgments that the Rajya Sabha Chairman should have kept in view before speedily sanctifying the transmogrified (mortified?) MPs. Honourable courts, persuaded by learned lawyers, might uphold the decision. The days when people in authority disagreed with each other seem passé and morality seems an effete concern.

This is no comment on the courts; this is how laws have been written, enabling the elected representative to act in accordance with the letter while abandoning its spirit. It is an act of hubris where elected representatives presume that their switchover has the endorsement of their voters.

What indeed is the spirit of being elected? Is it in any way affected by such change of loyalties? Most candidates winning elections belong to political parties. Independent candidates may make promises; they don't write manifestos. Parties do; and candidates winning on their ticket are bound by their manifestos as they contest on a common symbol. Where does it leave defecting candidates who, after elections, discard the support of those who voted for them? They were not the choice of those who didn't vote for them and are technically left without any support in their constituencies but continue to be their elected representatives. What kind of "representation" is this?

It could be argued that an individual's personal influence, no matter which party, earns him/her popular support. That makes the individual larger than the party, undermining the raison d'être of political parties. After all, parties represent a certain political thinking or ideology; at least they are meant to. While an individual may suffer "pangs of conscience", parties are not known to suffer this malady, although there have been instances of "mergers and acquisitions". While parties "merge", elected representatives are "acquired" in the Indian political marketplace.

In such an environment, why should we be obsessed with multiplying the number of representatives because of a fictional notion of being underrepresented? Has anyone evaluated whether smaller constituencies are better served by elected representatives than the larger ones? Yet there is a furious debate on delimitation to serve the abstract principle of "One Vote, One Value". A Parliamentary Committee also deliberates on the avoidable alternative of "One Nation, One Election", aimed at minimising the interface between the elector and the elected.What is the sanctity of my vote if the person I elect has the freedom to discard it and embrace the one that I rejected? It is time the anti-defection law is revisited. Let the law not prohibit elected representatives from switching sides, but the MP/MLA must go back to the electors for a fresh mandate, giving voters the opportunity of soul-searching.The splitting of a political party is a different matter and must be governed by the applicable law for the formation of political parties. Even if the party splits and the breakaway entity qualifies to be recognised as a separate party, the elected representatives must lose their seats. This would entail a 'wasteful' exercise of repeated elections, a cost a healthy democracy must learn to afford. Otherwise, we risk becoming a nation where riches and cunning matter more in politics than being consistent and scrupulous, and value is preferred over values.

Kiran Mazumdar-Shaw names niece Claire Mazumdar as successor: Report

New Delhi.(Agency)

Biocon founder Kiran Mazumdar-Shaw has finally shared her succession plan, putting an end to long-standing curiosity around who will lead the company next. She has confirmed that her niece, Claire Mazumdar, is being prepared to take over in the future, according to Fortune India.

Mazumdar-Shaw said she believes Claire is the right person to guide Biocon into its next phase. With no children of her own, she emphasised the importance of handing the company to someone she trusts. She added that Claire has already shown strong leadership skills and the ability to run a business.

The change in leadership will not happen overnight. Mazumdar-Shaw made it clear that she is not stepping down anytime soon. Instead, the transition will be gradual, allowing Claire to slowly take on more responsibility while ensuring stability within the company.

WHO IS CLAIRE MAZUMDAR?

Claire Mazumdar is currently the founder and CEO of Bicara Therapeutics, a company that was incubated by Biocon. She has a strong academic background, with degrees from MIT and Stanford, including a PhD in cancer biology.

Her experience also includes working with global biotech firms. Bicara, which went public in 2024, has already built a solid market presence.

Mazumdar-Shaw also spoke about the wider family's role in supporting the business. Claire's brother, Eric Mazumdar, is an expert in artificial intelligence, while her husband, Thomas Roberts, is a well-known oncologist. Together, they bring a mix of scientific and technological expertise.

BIOCON'S EVOLVING BUSINESS STRATEGY

Alongside leadership changes, Biocon is reshaping its business. The company has combined its generics and biologics units, cut down debt, and simplified its structure. A major focus is on biosimilars, which already make up a large part of its revenue. Several products are in the pipeline.

India's EV penetration climbs in April despite global fuel price concerns: FADA

New Delhi.(Agency)

Electric vehicle (EV) adoption in India's automobile sector continued to gain momentum in April, even as geopolitical tensions in West Asia raised concerns over fuel price stability and future demand patterns, according to the Federation of Automobile Dealers Associations (FADA).

FADA data indicates that the shift towards electric mobility is deepening across vehicle categories. The three-wheeler segment led the transition, with EV penetration surging to 60.38 per cent. In passenger vehicles, the EV share rose to 5.77 per cent, while in the two-wheeler category it stood at 7.76 per cent during April.

However, EV penetration in two-wheelers eased from 9.79 per cent in March, a drop attributed to pre-buying ahead of the phase-out of certain incentive schemes. Even so, April's figure remained above the FY26 average of 6.5 per cent, suggesting sustained underlying demand for electric mobility.

Overall, India's auto retail market posted its strongest-ever April performance, with total sales climbing 12.94 per cent year-on-year to 26,11,317 units.

Two-wheelers continued to dominate volumes, registering sales of 19,16,258 units, up 13.01 per cent year-on-year. Passenger vehicle sales rose 12.21 per cent to 4,07,355 units, while commercial vehicles grew 15.02 per cent to 99,339 units. The three-wheeler segment posted 1,06,908 units in sales, a 7.19 per cent increase. Tractor sales saw a sharp jump of 23.22 per cent to 75,109 units. In contrast, the construction equipment segment declined 2.25 per cent year-on-year to 6,348 units.

SWELECT plans to invest in power electronics of BESS

Mumbai.(Agency)

Chennai-based energy solutions company SWELECT Energy Systems plans to invest in a slew backward integrations in Battery Energy Storage Systems (BESS) such as manufacturing power electronics as it plans to take its share in the BESS 10-15% in the next five years.

The initial investment in the power electronics manufacturing would be nearly $20 million. Currently, most of the products starting from battery are sourced from China. Arulkumar Shanmugasundaram, MD & CEO of SWELECT, said, "We are planning to invest in manufacturing power electronics in India in our Salem factory. However, this exploration in new technology is at early stage." Power electronics is bidirectional power conversion between DC batteries and the AC grid. He added that the company is also exploring options to manufacture wafers, which is also an investment in backward integration in solar cell production, in India.

Shanmugasundaram also said that the company is also aggressively expanding the setting up of solar panels across north Indian markets under the PM Surya Ghar scheme as it has opened sales office and warehouses in UP, Bihar, Gujarat, Haryana, Delhi-NCR, among other states. "As these states have high incidents of load shedding, we see good opportunity for growth in the states. Solar panels and hybrid invertor solar could see a good demand in these regions. Though the growth in sale of solar panels is insignificant, we have rise in enquires from these states. The revenue conversation is very less for now, but our aim to attain an income of `1-2 crore every month."He also rued that the free power scheme in various states has dampened the growth of establishing solar panels across the country. "Most of the states offer free power up to 200 units. This is impacted the sale of solar panels to a certain extent. In individual houses, the power consumption goes up to 400 units only in summers. Now, with free power up to 200 units, the demand for solar panels has somewhere dropped."

2% DA hike explained: Only Rs 600 more on a Rs 30,000 basic pay?

New Delhi.(Agency)

If you were hoping for a noticeable jump in your pay packet, this update may feel a bit modest. The government has raised Dearness Allowance (DA) for central government employees and pensioners, but the increase is on the lower side. Still, arrears for past months could offer a small financial cushion.

DA INCREASED TO 60% FROM JANUARY 2026

Last month, the government announced a 2% increase in DA, effective from January 1, 2026. With this revision, DA as a share of basic pay has gone up from 58% to 60%.

Since the change is effective from January, employees and pensioners will receive arrears for the months already passed. Pensioners will also see a rise in Dearness Relief (DR), which will be reflected in their upcoming payouts.

A MODEST INCREASE IN TAKE-HOME PAY

While the revision offers some relief, the actual increase in monthly income is not very high. For many, it will only add a few hundred rupees to their salary.

Pratik Vaidya, Managing Director and Chief Vision Officer, Karma Management Global Consulting Solutions Pvt. Ltd., said, "Many were expecting a slightly stronger increase given the inflation trend, but the government has gone with a 2% DA hike this time, taking it from 58% to 60% of basic pay."

He further explained, "For a central government employee with a basic pay of Rs 30,000, that translates into an increase from Rs 17,400 to Rs 18,000, which means Rs 600 more per month. The real takeaway is that the increase is modest, but employees will also look at the arrears payable from 1 January 2026."

WHY ONLY A 2% INCREASE?

While there were expectations of a 2% to 4% rise, the final increase came in at the lower end. Experts say this is not a discretionary decision but a formula-based outcome.

Adhil Shetty, CEO, BankBazaar, explained, "The 2% increase in Dearness Allowance is a formula-led outcome linked to the 12-month average of CPI-IW inflation, not a choice within a 2–4% range. The underlying data pointed to a 2–3% movement. Under the 7th Pay Commission framework, the final DA number is rounded down to the nearest whole number, which is why the increase settles at 2% rather than moving higher."

He added that the revision reflects moderate inflation levels over the past year and is meant to keep incomes aligned rather than significantly increase earnings.

WHAT IT MEANS FOR EMPLOYEES

In simple terms, the DA hike will not dramatically change your monthly earnings. However, the arrears payment and the gradual adjustment to inflation do provide some support.So, while this may not be a headline-grabbing increase, it still ensures that salaries and pensions stay in step with rising costs, even if only gradually.

Sensex, Nifty bounced back in April. What can investors expect in May?

New Delhi.(Agency)

Even as the West Asia conflict and rising crude oil prices kept global markets on edge, April turned out to be a decent month for Dalal Street investors.The benchmark indices — BSE Sensex and Nifty 50 — gained over 3% during the month, recovering from March weakness and largely brushing aside global uncertainty, including tensions around US-Iran negotiations.The rally was broad-based, with several sectors participating. But as markets move into May, the outlook could be very different.

EARNINGS SEASON CHANGES THE GAME

The biggest factor for May is earnings. After a month driven largely by sentiment and broad optimism, the focus is now turning to company performance.This is where the market is likely to become more selective, according to experts."Stocks that rallied for genuine reasons like strong fundamentals, improving margins and better earnings visibility are likely to hold their ground," said Dr Ravi Singh, Chief Research Officer, Master Capital Services."But those that simply rode the broader wave of optimism without real substance may struggle once the numbers are out."In simple terms, the market is moving from momentum to fundamentals.

THE CRUDE OIL FACTOR

There are also a few factors that could cap sharp gains in the near term. Foreign investors have remained net sellers for much of 2026, while retail participation has been relatively muted despite the rally.At the same time, crude oil prices remain elevated, posing risks to inflation and India's current account.

"These are not alarm bells, but they do create a ceiling on any sharp upward move," Singh said.This combination suggests that while markets are not necessarily headed for a fall, the pace of gains could slow.

CONSOLIDATION, NOT CORRECTION

Given these factors, May is expected to be more of a consolidation phase than a continuation of April's rally. "May is more likely to be a consolidation month than either a sharp sell-off or a straight continuation of April's gains," Singh said.

OnEMI Tech IPO far from fully booked; brokerage flags key risks

New Delhi.(Agency)

The IPO of OnEMI Technology Solutions continues to struggle for traction, with subscription levels remaining well below full coverage on Day 2 and grey market signals pointing to negligible listing gains, even as brokerages caution investors about structural risks in the business.

The issue was subscribed just 0.63 times by the end of the second day of bidding. While institutional interest offered some support, with the qualified institutional buyers (QIB) portion subscribed 1.51 times, demand from other segments remained weak. Retail investors subscribed only 0.17 times, while the non-institutional investor (NII) category saw a subscription of 0.53 times, reflecting muted broader participation.Grey market trends mirror the lack of enthusiasm. The IPO's GMP stands at around Rs 1.5, indicating an estimated listing price of Rs 172.5, a marginal premium of just 0.88% over the upper price band of Rs 171. This suggests limited listing upside and cautious sentiment among investors.

WHY BROKERAGES ARE FLAGGING RISKS

Despite acknowledging growth potential, analysts have underlined multiple risks that make the IPO suitable only for investors with a higher risk appetite.

According to a note by Geojit Investments Limited, the company's business model remains exposed to credit risks due to its heavy reliance on unsecured lending. "Unsecured loans form a majority of AUM (94.2% as of December 31, 2025), making the business sensitive to demand fluctuations.

Gratuity rises under new labour rules, but what if you quit before 5 years?

New Delhi.(Agency)

You're a few months away from completing five years at your job, and a new offer lands in your inbox. Better pay, better role, but there's one question that quietly nags: will you lose your gratuity if you leave now?

It's a dilemma many employees face, especially at a time when new labour rules are changing how gratuity works. While payouts may increase for some, the basic eligibility rules still hold strong, and timing your exit can make all the difference.

THE FIVE-YEAR RULE ISN'T ALWAYS STRICT

Gratuity is a lump-sum benefit paid when your employment ends, and most people believe you must complete a minimum of five years to claim it. But that's not entirely accurate.

Pratik Vaidya, Managing Director and Chief Vision Officer of Karma Management Global Consulting Solutions Pvt. Ltd., explains that the law allows some flexibility.

"Many assume they must stay exactly five years – 60 months – to claim it. But under India's Payment of Gratuity Act, 1972, there is a more nuanced rule," he says.

The key lies in how "continuous service" is defined. If you complete four years and at least 240 working days in the fifth year, it can be treated as a full year. Courts have backed this interpretation.

"In one such case, the Madras High Court in Mettur Beardsell Ltd v. Regional Labour Commissioner, held that an employee who worked 240 days in the fifth year is deemed to have completed that year and is therefore eligible for gratuity. The judgement emphasised that the deeming provision in Section 2A should be applied to the fifth year and rejected a rigid interpretation of "five calendar years", Vaidya explains.

NEW LABOUR LAWS: WHAT HAS CHANGED?

The new labour codes have not completely rewritten the rules, but they have introduced some important changes.Srishti Oberoi, Advocate at District Courts Yamunanagar and Punjab and Haryana High Court, says the core rule still applies to most workers."The basic principle has remained the same for permanent workers. The five-year criterion still holds good for the majority of permanent jobs," she explains.

Why Warren Buffett says he doesn't understand markets any more

Warren Buffett said today's market is harder to read, with trading increasingly driven by short-term bets. His remarks underline his unease with stretched valuations, rising speculation and fewer clear opportunities.

New Delhi.(Agency)

Veteran investor Warren Buffett has raised concerns about how today's stock markets are behaving, saying he now understands "fewer of the businesses" than he did a decade ago and warning that a large part of the market has moved away from fundamentals.Speaking in an interview with CNBC, Buffett said the nature of investing has changed so much that even he finds it difficult to make sense of many valuations.

"I understand fewer businesses as a percentage of the whole than I did 10 years ago," he said, adding that he has not kept up with newer industries in the same way younger investors have.

MARKET NOW LIKE A "CASINO"

Buffett used a strong comparison to explain the current state of markets.

"The market always feels like a church with a casino attached," he said. "The casino has gotten very attractive to people."According to him, trading activity today is increasingly driven by short-term bets rather than long-term investing. He pointed to the growing popularity of one-day options.

"If you're buying one-day options or selling them, that is not speculating. That is gambling. Totally," Buffett said.

He added that there are now more people in a "gambling mood" than at any time in the past.

SHORT-TERM TRADING WORRIES

Buffett's concern is not just about speculation, but about the scale of it.

He said many traders are making decisions based on short-term price movements rather than business fundamentals. This, he warned, can lead to prices that do not reflect the real value of companies."That doesn't mean the market is terrible," he said. "But it does mean that the prices for an awful lot of things will look very silly."

WHY HE IS HOLDING CASH

One of the biggest signals from Buffett is his decision to hold a large amount of cash.His company, Berkshire Hathaway, is currently sitting on nearly $380 billion in cash. Buffett said this is because he does not see enough clear opportunities where he has an advantage.

"I'm not going to have an edge on a whole bunch of younger people that have actually grown up with it," he said.

He also noted that in his long career, only a few years offered truly strong investment opportunities, while most of the time he simply waited.

CONCERNS OVER INFLATION AND THE DOLLAR

Buffett also flagged risks related to inflation and the US dollar.He said the United States is "not immune" to serious inflation problems and pointed to past examples where economies faced repeated financial crises.

Unacceptable: India condemns Iran's attack on Fujairah that injured 3 Indians

India condemned Iran's attack on the Fujairah Petroleum Industries Zone in the UAE, which injured three Indian nationals, calling it "unacceptable" and urging an immediate halt to hostilities and the targeting of civilian infrastructure.

New Delhi.(Agency)

India on Tuesday condemned Iran's attack on the Fujairah Petroleum Industries Zone in the UAE, which left three Indian nationals injured, calling it unacceptable and demanded an immediate cessation of the targeting of civilian infrastructure. Prime Minister Narendra Modi voiced similar sentiments, condemning the attack and said that targeting civilians and infrastructure was unacceptable.Amid tensions with the US, Iran launched a fresh wave of missile and drone attacks targeting the UAE, with one strike triggering a fire at Fujairah Oil Industrial Zone on Monday, resulting in injuries to Indians.

"The attack on Fujairah that resulted in injury to three Indian nationals is unacceptable. We call for immediate cessation of these hostilities and the targeting of civilian infrastructure and innocent civilians. India continues to stand for dialogue and diplomacy to deal with the situation, so that peace and stability may be restored across West Asia," MEA spokesperson Randhir Jaiswal wrote on X.

"We also call for free and unimpeded navigation and commerce through the Strait of Hormuz in keeping with international law. India stands ready to support all efforts for a peaceful resolution of issues," he said.

PM Modi minced no words and said Iran's attacks on the UAE, which injured Indian nationals, were unacceptable.

"Strongly condemn the attacks on the UAE that resulted in injuries to three Indian nationals. Targeting civilians and infrastructure is unacceptable. India stands in firm solidarity with the UAE and reiterates its support for the peaceful resolution of all issues through dialogue and diplomacy," he tweeted.

The incident marks a sharp escalation in Middle East tensions and breaks a period of relative calm following a ceasefire between Washington and Tehran earlier this month. Emirati officials confirmed that air defences intercepted multiple incoming threats, even as damage was reported on the ground.

The Embassy of India, Abu Dhabi said it is coordinating closely with local authorities to assist those affected. "Three Indian nationals have been injured in today's attacks in Fujairah. We are in touch with local authorities to ensure adequate medical care and welfare of the affected Indian nationals," the embassy said in a post on X.

The UAE said Iran launched four cruise missiles during the latest attack. According to the defence ministry, three were intercepted by air defence systems, while the fourth fell into the sea.At the same time, a drone strike sparked a fire at the Fujairah Oil Industry Zone, a critical hub for the country's energy exports. Response teams were deployed to contain the blaze, officials said, adding that the injured individuals were taken to hospital with moderate injuries.Fujairah holds strategic importance as it allows the UAE to export oil through the Gulf of Oman, bypassing the Strait of Hormuz.

Day after Vivek Vihar fire claims 9 lives, cops say may use 3D mapping to determine cause; building vacated

New Delhi.(Agency)

A day after nine people died in a huge fire, which broke out at a residential building in Shahdara's Vivek Vihar in East Delhi, the entire building was vacated on Monday and an investigation was launched by the Delhi Police to ascertain the exact cause of the blaze.

Police officers said that they might also use 3D laser mapping technology, if required, to understand the circumstances under which the four-storey building caught fire. Police have used similar mapping technologies in major fire incidents earlier, including the Arpit Hotel fire in Karol Bagh and the Anaj Mandi fire in 2019. 3D mapping is a process of obtaining three-dimensional information about the site of an incident, especially when a structure has been severely damaged, with the help of software.

According to a senior officer, the rear portion of the four-storey building was the most affected. The structure, they added, might have been weakened as all three flats on the second, third, and fourth floors were gutted in the fire.The building, located in B Block of Vivek Vihar, has a parking space on the ground floor and two four-bedroom flats both on the front and rear side on each of the other floors. It was built in 2017 on an 800-square-yard plot. The flats were sold for Rs 3.5-4 crore, police sources said.

The fire turned the world of three families — residing on the second, third, and fourth floors — upside down as it cost nine lives. Families living in flats on the front side of the building, however, managed to escape. On Monday, all the families vacated their flats and moved to their relatives' homes for the civic authorities to complete inspections and declare the structure safe. In the afternoon, forensic and crime teams inspected the building and collected samples as part of the ongoing investigation.

Faces masked, clad in undergarments: 6 of notorious gang held for looting jewellery from South Delhi home

New Delhi.(Agency)

After executing a robbery worth lakhs of rupees in South Delhi's upscale Malviya Nagar area, six members of one of the Capital's most notorious robbery gangs — the Kaccha Baniyan gang — were arrested by Delhi Police on Sunday following an exchange of fire in South Delhi, said officers.

On May 1, six men, dressed in undergarments and wearing masks on faces, had allegedly entered a flat in Malviya Nagar's Sarvodaya Enclave. "Members of the family were sleeping in two bedrooms. The accused locked both the rooms, and then took jewellery ," the officer said. CCTV cameras in the house captured two of them, roaming around in undergarments, said police.

Officers of the Anti-Terrorism Squad (ATS) of Delhi Police (South) subsequently traced the six accused — alleged members of the Kachha Baniyan Gang — to Ambedkar Nagar, police said. "When officers reached the area, accused Nirmal Pardi, Devin and Samar opened fire at them. The police team fired in retaliation, and bullets hit the three on legs," an officer said. The accused identified as Kaake, Krish and Shivaji, and their accomplices, were arrested. All of them hail from Madhya Pradesh. Officers suspect the six men were involved in at least four robberies in Delhi last year.

Members of the Kaccha Baniyan gang are largely from the Pardi community, a nomadic tribe originally from parts of Madhya Pradesh and Maharashtra, traditionally known for their hunting skills. The gang became notorious in the 90s and 2000s after a series of robbery-cum-murders were reported across the country, in which the thieves entered homes wearing only undergarments. Among the prominent cases from Delhi was murder of two people during a robbery in Lodhi Colony in 1991.

India issues NOTAM for long-range missile test in Bay of Bengal

New Delhi.(Agency)

India has issued a Notice to Airmen (NOTAM) designating a vast stretch of the Bay of Bengal as a danger zone for a long-range missile test, with the warning active from April 25 to May 6, 2026. The NOTAM covers a corridor extending up to approximately 3,550 km, signaling preparations for an intermediate-range ballistic missile (IRBM) launch.Defence sources told India Today that it indicates the flight path and exclusion zone align with the performance envelope of the Agni-IV, an IRBM with a reported range of 3,500–4,000 km. The Agni-IV is a two-stage, solid-fuelled missile capable of carrying a 1,000-kg warhead and is a key component of India's nuclear triad and strategic deterrence posture.

The timing is notable. The test window overlaps with the first anniversary of Operation Sindoor, conducted in early May 2025. While the Ministry of Defence has not officially linked the test to the anniversary, strategic analysts suggest the launch would serve both as a validation exercise and as a message of readiness and capability enhancement.

Recent months have seen India step up testing of its strategic missile inventory. The Agni series, along with the submarine-launched K-4 and the hypersonic LRAShM, form the backbone of India's credible minimum deterrence doctrine.

The extended-range BrahMos cruise missile, with tests underway to push its reach to 800 km, and this potential Agni-IV trial point to a broader modernization drive across both tactical and strategic vectors. Induction of the 800-km BrahMos is expected by end-2027.A NOTAM is issued when authorities need to restrict civilian aircraft from a specific stretch of airspace, usually during sensitive or high-risk operations. Such advisories have been used in the past during periods of heightened military tension, including conflict with Pakistan, to keep commercial flights away from operational zones.

'Change became inevitable': Delhi Malayalis welcome UDF win in Kerala polls

New Delhi.(Agency)

As the election results ensured victory for the Congress-led UDF in Kerala, Malayali people living in the city welcomed the mandate. Malayali associations and individuals in the city said the results once again proved that political change takes place in the state periodically. Roughly 7–8 lakh Malayalis live in Delhi and its neighbouring cities, and many of them had travelled to their native state to exercise their franchise.

Welcoming the Congress party's victory, they said the results were on expected lines, as the LDF had completed its 10-year term and change had become inevitable. They added that both the UDF and LDF are equally close to people from the state living in the capital, as both have contributed to Kerala's development.

Hence, they said, the change of guard should not be read too deeply. K Raghunath, president of the Delhi Malayalee Association, said the Sheila Dikshit-led Congress government in Delhi had done significant work for people from Kerala residing in the city for livelihood. He said the party leadership had generally remained close to South Indians, and therefore many were pleased with the poll outcome.

If we talk about construction of temples, ensuring basic facilities, and facilitating people coming from the state, the Sheila Dikshit-led Congress government always stood by them. A similar situation was seen in Kerala under previous Congress governments, which did considerable work for the betterment of the people," he said.

KK Tony, a Kerala native living in Karol Bagh, said the LDF government also did good work under CM Pinarayi Vijayan, but some party workers were dissatisfied at the grassroots level.He said that with a change of guard, Congress emerged as a natural choice. "Since the BJP has no strong base in the state, Congress is a likely option. We believe the party will continue to support people living outside Kerala," he said.

Can't sell, can't take loans: How Gurgaon's 180 sq yard rule is hitting hundreds of families

New Delhi.(Agency)

For 51-year-old private school teacher Richa Bhardwaj, the dream of upgrading to a bigger house as her sons grow up has been a testing one. The hurdle is not a lack of finances, but an administrative circular issued in March 2009 that limits the registration of residential plots to those measuring 180 sq yards and above.

Residing in the F block of Suncity township off Golf Course Road, Bhardwaj can neither sell her 2BHK apartment — purchased in 2003 and measuring less than 180 sq yards — nor avail of a mortgage because it's not registered. "My children are growing up, and they need a separate room. I cannot think of getting my elder son married because of this," she said.She is not alone.For over 70 similarly placed homeowners in Suncity, and hundreds of families across private plotted colonies in Gurgaon, the dream of undisputed property ownership has turned into a 15-year-long ordeal. Despite paying the full sale consideration, taking possession, and regularly paying municipal taxes, these residents are continually denied property registration.

The legal impasse

At the core of the dispute is the 2009 administrative circular invoked by authorities to deny registrations. Homeowners argued that this circular is obsolete, pointing out that the state government itself amended the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, in September 2009.The amendment introduced Section 3-C, which explicitly permits the registration of independent residential floors in licensed colonies without prescribing any minimum plot size restriction, while also enabling.

SpiceJet plea on Rs 144-crore pay order in Maran row junked

Justice Subramonium Prasad also imposed a cost of Rs 50,000 on the airline & Singh and directed them to take immediate steps to deposit the amount of Rs 144 crore with the registry.

New Delhi.(Agency)

The Delhi High Court on Monday junked pleas filed by SpiceJet and its promoter Ajay Singh seeking a review of an earlier order asking the airline to deposit `144 crore in connection with its legal dispute with media baron Kalanithi Maran and Kal Airways.Justice Subramonium Prasad also imposed a cost of Rs 50,000 on the airline & Singh and directed them to take immediate steps to deposit the amount of Rs 144 crore with the registry.

In its January 19 order, the court had directed the airline and Singh to deposit `144 crore with the registry within six weeks against an admitted liability of `194 crore. However, the deadline to make the deposit was later extended by four weeks on March 18.

The petitioners had sought reconsideration of the March 18 direction, citing financial distress amid the ongoing conflict in West Asia. Instead of money, the airline offered a commercial property in Gurugram as security.

However, Maran and Kal Airways had opposed the petitions, saying the issues arising from financial distress had already been considered and rejected by the Supreme Court.

The matter arises from a dispute regarding the non-issuance of warrants in favour of Maran following the transfer of SpiceJet's ownership to Singh, the controlling shareholder of the airline.The dispute started after Singh took back control of SpiceJet in February 2015 amid a financial crisis at the airline.

No FIR: Court relief for Abhijit Mitra

A Delhi court on Monday stayed the filing of an FIR against political commentator Abhijit Iyer Mitra for allegedly making abusive remarks against nine women journalists of online media outlet Newslaundry. This came as Additional Sessions Judge Purushottam Pathak heard a plea moved by Mitra.

HC protects Arjun's personality rights

The Delhi HC has protected the personality rights of actor Arjun Kapoor and restrained the unauthorised use of his name, voice, image and other attributes by third parties for impersonation, sale of merchandise, creating deep fake images, etc.

NEWS BOX

'Will blow Iran off the Earth': Trump warns over attacks on ships in Strait of Hormuz

World. (Agency)

US President Donald Trump has warned that Iran would be "blown off the face of the Earth" if it attacked American vessels providing security to ships stranded in the Strait of Hormuz.

Talking to Fox News, Trump added that the United States "can't let Iran have a nuclear weapon". His remarks come amid heightened tensions after Iran allegedly targeted some vessels being escorted through the strait under "Project Freedom", an initiative launched by the US Central Command on the President's orders.

US targets Iranian boats

Trump said the US military had destroyed seven small boats linked to Iran, further escalating tensions around the strategic waterway. Posting on his social media platform Truth Social, he claimed Iran had attacked several ships, including a South Korean cargo vessel being escorted through the strait, which has effectively been shut since the war with Iran began on February 28.

"If you're escorting a ship, you're playing kind of one on one. I think we have a much better defensive arrangement in this process," he said. "We have a much broader defensive package than you would have ever if you were just escorting."

The US President also said Iran had targeted vessels from other countries under Project Freedom and urged South Korea to join the mission. "Perhaps it is time for South Korea to participate," he said.

Trump added that the US possesses advanced weapons and ammunition and maintains a strong global military presence. "We have the best equipment… our bases around the world are fully stocked. We can use them, and we will if necessary," he said.

'Can't let Iran have a nuclear weapon'

Speaking at the White House Small Business Summit, President Trump said, "We can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs, and I said we have to take care of business because we can't let that happen."

Ex-JPMorgan banker Chirayu Rana faked father's death to get paid leave before filing bombshell lawsuit: Report

New York. (Agency)

Fresh details have emerged in the high-profile legal dispute involving former JPMorgan Chase banker Chirayu Rana, who has accused a former colleague of sexual misconduct.

According to a report by the New York Post, Rana allegedly misled the bank by falsely claiming his father had died in order to secure nearly three months of paid leave, time he is now alleged to have used to prepare his lawsuit against the bank and former colleague Lorna Hajdini.

Chirayu Rana news

Sources told the publication that Rana informed supervisors in December 2024 that his father, Chaitanya Rana, had passed away and that he needed leave to be with family.The report claims he combined bereavement leave with other paid leave benefits to remain away from work for an extended period.However, the report states that his father is alive.When contacted, Chaitanya Rana reportedly said, "I don't know anything about it. He didn't talk with us or anything. He's my son. He's a good guy."

Chirayu Rana case

Rana filed a lawsuit in April under the pseudonym "John Doe", accusing executive director Lorna Hajdini of drugging him and coercing him into sexual acts while threatening his career.The lawsuit includes allegations involving Rohypnol and Viagra.However, the bank has denied the claims.

Elon Musk settles SEC lawsuit over Twitter disclosures, $1.5 million fine imposed

World.(Agency)

Elon Musk settled the US Securities and Exchange Commission's civil lawsuit accusing the world's richest person of waiting too long in 2022 to disclose his initial purchases of Twitter, now known as X.

A trust in Musk's name will pay a $1.5 million civil fine, under the settlement disclosed on Monday in the Washington, DC, federal court.

Musk did not admit wrongdoing, and won't have to give up any of the $150 million he allegedly saved from the delay.

The settlement requires approval by US District Judge Sparkle Sooknanan, who in February rejected Musk's bid to dismiss the case. It ends more than seven years of fraught battles between Musk and the regulator, starting in September 2018 when the SEC charged him with securities fraud for tweeting he had "secured" funding to potentially take his electric car company Tesla private.

Musk settled that case by paying a $20 million civil fine, letting Tesla lawyers review some Twitter posts in advance, and giving up his role as Tesla's chairman."Musk has now been cleared of all issues related to the late filing of forms in the Twitter acquisition, as we said from the outset he would be," his lawyer Alex Spiro said in a statement.The SEC declined to comment.

21 killed in China fireworks factory blast; 500 rescuers lead massive relief effort

At least 21 people were killed and over 60 were injured in a powerful explosion at a fireworks factory in China's Hunan province.

World. (Agency)

A powerful explosion at a fireworks manufacturing unit in central China's Hunan province killed 21 people and injured around 60, triggering a massive rescue operation, state media reported on Tuesday.Nearly 500 rescuers were deployed to the scene and evacuations were conducted in danger zones. Officials were also evacuating residents within a 3-km radius of the plant, where two warehouses storing black gunpowder continue to pose a significant risk.

The blast happened at a workshop of the Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company in Liuyang, a major hub for firework production, according to reports by Xinhua.

Footage circulating on Chinese social media showed thick plumes of white smoke billowing from the site.The impact of the explosion shattered doors and windows in nearby villages, with residents reporting debris, including large rocks, strewn across roads. Some villagers evacuated the area over safety concerns.

Chinese President Xi Jinping called for an immediate and thorough investigation into the incident,

directing authorities to intensify efforts to locate missing persons and treat the injured.

He also urged stricter risk screening and hazard control across key industries, alongside improved public safety management to safeguard lives and property, the South China Morning Post reported.

China's Ministry of Emergency Management has dispatched a team to oversee rescue and relief efforts.

Meanwhile, police in Liuyang have detained senior executives of the company as part of an ongoing investigation into the cause of the blast.To prevent secondary explosions during rescue operations, firefighters have been using water cannons to douse the site, while three rescue robots have been deployed to assist in search efforts.

The incident comes less than three months after a separate explosion at a firecracker store in China's Hubei province killed 12 people.

If you target US ships near Hormuz, you'll be blown off Earth: Trump warns Iran

World. (Agency)

Donald Trump said Iran would be "blown off the face of the earth" if it attacked US vessels involved in a bid to reopen a route through the Strait of Hormuz, as Washington began an operation on Monday to assist hundreds of ships stranded with their crews in the Gulf.

The move has once again pushed the region to the brink of escalation, as Tehran sought to reassert its dominance over the strait — a key route for global trade -- and maintain the blockade imposed by it.

The US military said it had destroyed six Iranian small boats and intercepted Iranian cruise missiles and drones, a claim denied by Iran.More than 800 ships and about 20,000 crew members remain stuck in the energy chokepoint in the Gulf.

In an interview with Fox News on Monday, Trump described the US naval effort as "one of the greatest military manoeuvres ever done" and said Iranian officials had been "far more malleable" in recent talks than before.

Addressing concerns over American weapons stockpiles, he told Fox News: "We have more weapons and ammunition at a much higher grade than we had before. We have the best equipment. We have stuff all over the world. We have these bases all over the world. They're all stocked up with equipment. We can use all of that stuff, and we will, if we need it."

Trump's latest threat echoed remarks he made in April, when he warned that a "whole civilisation will die" if Tehran did not comply with his demands over the Strait of Hormuz. Those comments drew widespread domestic and international backlash.

His remarks also cast doubt on the fragile ceasefire brokered by Pakistan last month, which halted hostilities but did not reopen the Strait of Hormuz, through which about a fifth of global oil supplies typically pass.

Hormuz flashpoint, US intercepts drones as Iran challenges mission

World.(Agency)

The United States military said it destroyed six Iranian small boatsand intercepted multiple cruise missiles and drones as Iran attemptedto disrupt a new naval initiative aimed at reopening the Strait ofHormuz.

The operation, named"Project Freedom," was launched on Monday under orders from USPresident Donald Trump to restore shipping through the strategicwaterway, which Iran had effectively shut following the escalation ofconflict involving the US and Israel on February 28.According toReuters, the US Admiral Brad Cooper, head of Central Command,confirmed that Iranian forces, including the Islamic RevolutionaryGuard Corps (IRGC), had launched coordinated attacks involvingmissiles, drones, and fast boats targeting vessels under USprotection. He said all threats were neutralised."The IRGC haslaunched multiple cruise missiles, drones and small boats at ships weare protecting. We have defeated each and every one of those threatsthrough the clinical application of defensive munitions," Coopersaid.

The operationinvolves around 15,000 US troops, supported by Navy destroyers, over100 aircraft, helicopters, and undersea assets. US forces have alsodeployed electronic warfare systems as part of a multi-layereddefence strategy.Cooper warnedIranian forces to stay clear of US assets, adding that commanders onthe ground have full authority to defend both military units andcommercial shipping.In a keydevelopment, the US said it had successfully cleared parts of thestrait of Iranian mines and demonstrated safe passage by escortingtwo US-flagged commercial ships through the corridor.

White House briefly locked after Secret Service shoots armed person nearby

World.(Agency)

An officer-involved shooting near the White House on Monday triggered a temporary lockdown and heightened security across central Washington, authorities said.

The US Secret Service confirmed its personnel responded to an incident at 15th Street and Independence Avenue, where one individual was shot by law enforcement. The person's condition was not immediately known.In an initial statement, the agency said its officers were on the scene of the shooting. It later clarified that the incident stemmed from a confrontation between an armed individual and Secret Service Police.

The Metropolitan Police Department said officers were assisting at the scene and have secured the area. Authorities urged the public to avoid the vicinity, warning that road closures would remain in place for several hours.

The White House complex was briefly placed under lockdown as a precaution, though officials did not report any threat to protected individuals.

Security agencies in Washington, DC have been on heightened alert in recent days following a separate shooting incident late last month at the White House Correspondents' Association Dinner, for which a suspect has already been taken into custody.

Russia and Ukraine declare competing ceasefires to mark Victory Day

The announcements on Monday come as Russia prepares to celebrate its most important secular holiday with a traditional military parade on Moscow's Red Square pared down due to what officials say are concerns over possible Ukrainian attacks.

World.(Agency)

Russia's Defense Ministry declared a unilateral ceasefire in Ukraine for Friday and Saturday to mark the 81st anniversary of the defeat of Nazi Germany in World War II, but it threatened to strike back at Kyiv if it tries to disrupt the Victory Day festivities.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in response said his country would observe a truce beginning at 12 a.m. on Wednesday and respond in kind to Russia's actions from that moment on. He did not put an end date on the truce.

The announcements on Monday come as Russia prepares to celebrate its most important secular holiday with a traditional military parade on Moscow's Red Square pared down due to what officials say are concerns over possible Ukrainian attacks. Ukraine has been launching drone attacks deep inside Russia to counter its more than 4-year-old invasion.

They also follow a familiar pattern of previous attempts to secure ceasefires — most recently around Orthodox Easter — that had little to no impact.

The Defense Ministry said if Ukraine attempts to disrupt Saturday's celebrations, Russia will carry out a "massive missile strike on the center of Kyiv." It warned the civilian population there and employees of foreign diplomatic missions of "the need to leave the city promptly."

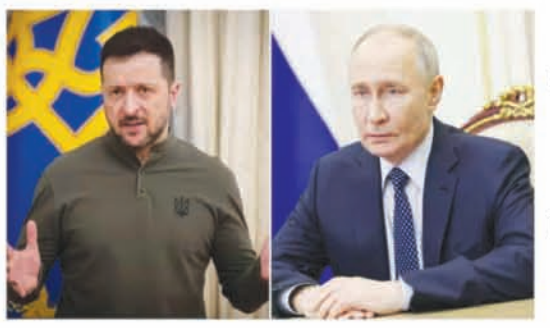

Zelenskyy responded by saying that while Kyiv has not received any official requests for a truce, in the time left until midnight on Wednesday "it is realistic to ensure" that a ceasefire takes effect. He urged the Kremlin "to take real steps to end their war, especially since Russia's Defense Ministry believes it cannot hold a parade in Moscow without Ukraine's goodwill."

For years, the Kremlin has used the pomp-filled Victory Day parade to showcase its military might and global clout, and it has been a source of patriotic pride.

But this year, the parade in the Russian capital will take place without tanks, missiles and other military equipment for the first time in nearly two decades. Some of the smaller parades that are held elsewhere across the country have also been pared down or even canceled for security reasons.

Speaking at a summit with European leaders in Armenia on Monday, Zelenskyy said that the Russian authorities "fear drones may buzz over Red Square" on May 9. "This is telling. It shows they are not strong now, so we must keep up the pressure through sanctions on them," he said.

NEWS BOX

Neymar accused of assault on Santos teammate after heated training clash

New Delhi. (Agency)

Neymar has landed in controversy after an alleged altercation with teammate Robinho Jr. during a Santos training session. The incident has led to serious accusations and forced Santos FC to step in.The clash is reported to have taken place during Sunday's training, with tensions escalating after an on-field moment between the two players. While Neymar has not commented publicly, the matter has quickly gained attention after formal complaints were made.

Santos have since confirmed that an internal investigation has been launched into the incident. With Robinho Jr. reportedly accusing Neymar of physical misconduct and even considering his future at the club, the situation has taken a serious turn ahead of Santos' upcoming fixtures.

WHAT HAPPENED BETWEEN NEYMAR AND ROBINHO JR?

According to ESPN, the incident began after Robinho Jr. dribbled past Neymar during training, which reportedly did not sit well with the senior player.

Neymar is alleged to have reacted by tripping the youngster, leading to a heated exchange between the two. The situation escalated quickly, with teammates stepping in to separate them as tensions boiled over.Robinho Jr. has accused Neymar of using offensive language, tripping him, and delivering a slap during the altercation. The 18-year-old is said to have been deeply upset by the incident.

Sources also suggest Neymar later attempted to calm things down by reaching out to Robinho Jr. and his family with an apology, though the matter remains unresolved.

WHAT STEP HAS SANTOS TAKEN?

Santos have initiated an investigation through their legal department into the events of May 3.The club has stated that the matter is being reviewed and that appropriate action will follow based on the findings. Robinho Jr.'s representatives have also sent an extrajudicial notice to the club, demanding action and raising concerns over player safety.

There are also reports that Robinho Jr. could consider terminating his contract if the situation is not handled adequately.Despite the controversy, Neymar is expected to feature in Santos' upcoming Copa Sudamericana fixture against Deportivo Recoleta, with the focus now split between on-field duties and the outcome of the investigation.

Premier League title race out of Manchester City's hands after Everton draw: Guardiola

New Delhi. (Agency)

Manchester City manager Pep Guardiola has admitted that the Premier League title race is out of their hands following their 3-3 draw against Everton on Monday, May 4. City need a last-gasp equaliser from Jeremy Doku to avoid getting beaten on the night as they had the chance to go level with Arsenal had they won their clash with Everton and the match against Brentford on Saturday.

It was Doku who gave the visitors the lead in the 43rd minute before City capitulated in the second half of the game with some costly mistakes. They gave Everton the chance to get back into the contest as a costly error from Marc Guehi allowed Thierno Barry to get the equaliser.

Jack O'Brien then gave the home side the lead before Barry got his second of the night. City pulled one back through Erling Haaland, before Doku got the equaliser with a thunderous strike, to get the City fans back into the stadium after they started making their exits early.Speaking after the match, as quoted by Reuters, Guardiola said that he expects City's remaining four games to be similar to the Everton test."It's now not in our hands, before it was, now no," Guardiola said.

"Four games we have (remaining) in the Premier League. They will be quite similar and we'll see what happens."

City are five points behind Arsenal, albeit with a game in hand, but will now have to hope that Arsenal slip up in their remaining three matches, which appear to be easier on paper. The Gunners face relegation-threatened West Ham, already-relegated Burnley and Crystal Palace in the final stretch.

Guardiola said that the point gained was better than a loss in the end."It's better than losing," he said. "We'd rather win. We play for that and we just showed what a team we are. We tried everything. The players were aggressive."City will be facing Brentford, Palace, Bournemouth and Aston Villa in their final four games and have a FA Cup final with Chelsea to play before the end of the season.Doku rallied his side and refused to throw in the towel just yet, saying that they will fight till the end.

What's wrong with Jasprit Bumrah? Sunil Gavaskar explains MI pacer's IPL 2026 issues

Sunil Gavaskar has said Jasprit Bumrah is overcomplicating his bowling during a lean IPL 2026 for Mumbai Indians. With Sanjay Bangar suggesting a short break, MI must decide how to restore his rhythm.

New Delhi. (Agency)

Jasprit Bumrah is going through an unusually quiet Indian Premier League (IPL) 2026, with the MI spearhead managing just three wickets in 10 matches. Indian cricket legend Sunil Gavaskar believes the problem lies not in effort, but in Bumrah trying to do too much and losing his natural rhythm.

The dip was evident again during Mumbai Indians' win over Lucknow Super Giants at the Wankhede, where Bumrah went wicketless for the seventh time this season and conceded 45 runs. MI chased down 229 with ease, but Bumrah's spell stood out for the wrong reasons, including a 21-run over and another no-ball that cost him a wicket.

Speaking to Star Sports, Gavaskar pointed out where things are slipping for the fast bowler.

"Bumrah is giving his best, but he seems to be trying too many extra things. He is creating wicket-taking chances, but luck is not on his side. His pace has also dropped he is overdoing things, and that's hurting him. He should go back to his basics and stick to what works best for him. Trying new things is affecting his rhythm and luck isn't helping either."For a bowler known for control and clarity, this phase has been about small things going wrong repeatedly. The no-balls, the drift in line, the slight drop in pace, all adding up, even on nights when MI are winning comfortably.

WHAT IS GOING WRONG WITH BUMRAH IN IPL 2026?

Gavaskar's explanation goes straight to the technical details behind Bumrah's dip."His go-to slower ball length has become fuller. The line that used to target the stumps is now drifting to leg stump. He is not known for bowling many no-balls, but this season he has already bowled six or seven."

That shift has been visible through the season. Bumrah has conceded 329 runs in 37 overs at an economy of 8.89, while using slower balls far more frequently than usual.

Even when he has created chances, things haven't fallen his way. Against LSG, a breakthrough turned into a no-ball, and in another spell, control came but without wickets. It has been a season where the margins have consistently gone against him.

SHOULD MI GIVE SOME REST TO JASPRIT BUMRAH?

Former India batting coach and all-rounder Sanjay Bangar believes the solution may not be purely technical."We are in that space that the management can probably honestly sit and have a chat. Ask him: 'are you feeling 100% from within'; 'do you want to take a break for a game or so'," Bangar said.The suggestion comes from the idea that Bumrah might benefit from stepping away briefly, resetting physically and mentally, before returning sharper for the final stretch.

"And if he says 'no, I am good to go, I will play', you will probably see a better version of him, because he will try to push even more harder," Bangar added.For MI, it's a delicate balance. They need Bumrah at his best, but right now, the bigger question is whether simplifying his approach, or even taking a short break, is the key to getting him back there.

You should go home: How Ruturaj Gaikwad sparked Overton-Tilak clash during MI vs CSK

New Delhi. (Agency)

Did Chennai Super Kings captain Ruturaj Gaikwad incite the altercation between Jamie Overton and Tilak Varma during the MI vs CSK clash at the Wankhede? The England all-rounder has revealed the role that Ruturaj played in his war of words with Tilak during a CSK event with kids.The incident between Tilak Varma and Jamie Overton unfolded after the final ball of the 10th over of the Mumbai innings during the match on April 23, when tempers flared briefly.

Tilak nudged the ball to mid-wicket and looked for a second, but was sent back by Suryakumar Yadav. While returning, he had to swerve past Overton at the non-striker's end, triggering a heated exchange between the two. Suryakumar and the umpires quickly stepped in to calm things down.Did Chennai Super Kings captain Ruturaj Gaikwad incite the altercation between Jamie Overton and Tilak Varma during the MI vs CSK clash at the Wankhede? The England all-rounder has revealed the role that Ruturaj played in his war of words with Tilak during a CSK event with kids.

The incident between Tilak Varma and Jamie Overton unfolded after the final ball of the 10th over of the Mumbai innings during the match on April 23, when tempers flared briefly.

Tilak nudged the ball to mid-wicket and looked for a second, but was sent back by Suryakumar Yadav. While returning, he had to swerve past Overton at the non-striker's end, triggering a heated exchange between the two. Suryakumar and the umpires quickly stepped in to calm things down. However, both players were later seen embracing during the post-match handshakes, signalling that all was well despite the earlier confrontation.

While attending the CSK event, Overton was asked by a young fan about what actually happened between him and Tilak. The CSK all-rounder quickly put his captain on the spotlight."No, no, no. Maybe you should ask Rutu.

When will Hardik Pandya return from injury? Rickelton shares update on MI captain

New Delhi. (Agency)

Hardik Pandya's absence raised eyebrows ahead of Mumbai Indians' clash against Lucknow Super Giants, with the MI captain missing yet another IPL 2026 game. The all-rounder's fitness has now become a fresh concern for the franchise as the tournament enters a crucial phase.

In his absence, Suryakumar Yadav stepped in to lead MI, marking the second time this season Pandya has missed a game. While MI did not initially provide full clarity, the situation became clearer as updates emerged during and after the match.

Speaking after MI's win, opener Ryan Rickelton admitted that even the players were not fully aware of the severity of the issue."I don't know when he's expected to be back. I found out this afternoon that he had back spasms, so I'm unaware of the extent of it. I don't want to call it an injury; I'm unaware of how bad it is or what he's feeling. But I'm sure he'll be with the group again as we head to Raipur this week," Rickelton said.

The update suggests that while the injury is not being treated as a long-term setback, there is still no fixed timeline for Pandya's return.

WHY DID HARDIK PANDYA NOT PLAY MI vs LSG?

Mumbai Indians confirmed before the match that Pandya was unavailable due to a back spasm.

The issue reportedly surfaced close to the game, with MI stating that the all-rounder was "unwell," prompting Suryakumar to take over captaincy duties. This was also the second match Pandya has missed this season, having earlier sat out the game against Delhi Capitals.Back spasms, while not always serious, can be tricky to manage, especially for an all-rounder who contributes with both bat and ball.

Release Rishabh Pant as captain, we're losing him as batter: Pundits tell LSG

New Delhi. (Agency)

Former India cricketers Rohan Gavaskar and Manoj Tiwary said that LSG should make the bold call and release Rishabh Pant from his captaincy duties. Both pundits feel that Pant the batter is taking a toll due to being skipper of the team after they lost to MI.Under Pant's captaincy, Lucknow have won just eight out of 23 matches and find themselves rooted to the bottom of the IPL 2026 points table. As a batter, the southpaw has scored just 204 runs in nine matches at a strike-rate of 128.30 and an average of 25.50.

Speaking on Cricbuzz, Gavaskar said that LSG need to take Pant out of the firing line after the season and should be allowed to fcous purely on his batting from IPL 2027.

"Sanjiv Goenka had once said in an interview that he wants Pant to create a legacy, play for LSG for the next 10–15 years and win trophies. But sometimes you've got to put certain players out of the firing line. After this season, LSG must decide whether they want to keep him as captain. He should be allowed to focus only on his batting, because we all know his capabilities and talent."

"When the team performs badly, that pressure also falls on the skipper. So release him from that and allow him to play freely," Gavaskar said.

'WE ARE LOSING PANT THE BATTER'

Tiwary chimed in and said that the pressure of captaincy has affected the batting of Pant and play him as a pure batter.

"I feel that, under the pressure of captaincy, we are losing Pant the batter — someone who has performed in international cricket and the IPL previously. He is not getting those runs this season. So release him from the captaincy burden and let him play purely as a batter.

That would be best for LSG," Tiwary added.The comments from Gavaskar and Tiwary echoed the same sentiment from Wasim Jaffer, who told LSG to replace Pant as skipper and give the responsibility to Aiden Markram.The latest loss means that Lucknow are all but out of the race for a playoff spot this season.

Foul play in RR sale? Kal Somani-led group say they were pushed out of deal

The Kal Somani-led consortium has claimed it was pushed out of the Rajasthan Royals ownership deal despite leading the bid for six months. The statement challenges reports that it withdrew and raises questions over how the franchise sale was handled.

New Delhi. (Agency)

The Kal Somani-led consortium claimed that they were pushed out of a deal to secure a majority stake in Rajasthan Royals. It was reported on March 24 that Somani, along with Rob Walton of the Walmart family and the Hamp family (owners of the NFL's Detroit Lions) acquired the inaugural IPL champions in a deal worth $1.63 billion (approx. Rs 15,000 crore).

However, on May 3, it was confirmed that the Mittal family, headed by Lakshmi N. Mittal and Aditya Mittal, had entered into a definitive agreement to acquire the franchise in a deal worth approximately USD 1.65 billion (around Rs 15,660 crore). There were also reports suggesting that the Somani-led consortium had pulled out of the race for the franchise.

"We are deeply disappointed not to be part of the Rajasthan Royals ownership group, following a long six-month process in which we were the lead bid from start to finish.""Our consortium worked tirelessly to assemble a distinguished group of investors, with ownership experience across the NFL, MLB, EPL, La Liga and TGL. Included in the group were select global superstars from the top tiers of professional sports. We were all motivated by the opportunity to help take the IPL to new international heights. Throughout the process, we were the strongest group at every stage, competing against some of the most prominent investors across the sports investing landscape," read the statement.

SOMANI-LED GROUP SQUASHES RUMOURS ON RR BID

The group also said that the reports floating around in the media at the moment, they were fully funded and ready to close the deal and never withdrew their bid.They also alleged that it wasn't a level playing field in the end and said such a process needed to be conducted with transparency, consistency, integrity and good faith.

"Contrary to stories that have been planted in the press, our group was and has always been fully funded, prepared to close with certainty, and never withdrew our bid.

We had executed documentation in place and were told that the franchise's board meeting on Saturday was held to approve our consortium. In the end this was never the case. We approached this process with the highest standards of honesty, integrity, professionalism and in good faith, but unfortunately that wasn't enough."

Jacqueline Fernandez

To Return To Cannes Film Festival 2026, Actress Finalising Red Carpet Looks

Jacqueline Fernandez is set to return to the Cannes Film Festival this year. The actor, who has been a regular presence at the prestigious international film gala over the past few years, is reportedly preparing for her appearance at the 79th edition of the festival.

A source shared, as quoted by Hindustan Times, "The actor is currently in the process of finalising her various looks before heading to France."The 79th annual Cannes Film Festival will be held from May 12 to May 23, 2026.

Jacqueline Fernandez's Cannes Journey

Jacqueline's association with Cannes has grown stronger in recent years. Last year, she was honoured by the Red Sea Film Foundation's Women in Cinema initiative. She was among six global honourees recognised for their contribution to cinema, marking an important moment for South Asian representation on an international platform.

Before that, Jacqueline attended Cannes in 2024, where she represented India and was also present at the premiere of The Substance. Her appearances at the festival have often drawn attention for both her fashion choices and her role in bringing Indian cinema visibility on the global red carpet.

With her return this year, expectations are high around her Cannes looks and appearances.

Payal Kapadia To Head Critics' Week Jury

Apart from Jacqueline's return to Cannes, Indian cinema will also have another important representation at the festival this year. Filmmaker Payal Kapadia has been named president of the jury for the 65th edition of Critics' Week, the independent sidebar of the Cannes Film Festival.

Kapadia, who won the Cannes Competition Grand Prix for her acclaimed film All We Imagine As Light, will lead a jury that includes Ama Ampadu, senior production and development executive at the BFI Filmmaking Fund, Quebecois actor Theodore Pellerin, French musician Oklou and Thai journalist Donsaron Kovitvanitcha.Critics' Week 2026 will run from May 13 to May 21.With Jacqueline Fernandez returning to the red carpet and Payal Kapadia taking on a key jury role, India's presence at Cannes 2026 is already shaping up to be significant.

Janhvi Kapoor's

Team Issues Official Note On Her Alcohol Remark: 'Misinformation In This Space Is Harmful'

Janhvi Kapoor recently made headlines when her statement on the Raj Shamani Podcast was taken out of context, with many assuming she had spoken about addiction. Now, Off the Rocks, an initiative by the actress, has issued an official statement clarifying her stand.The official statement was also shared by Janhvi Kapoor on her Instagram story, which reads, "We at Off The Rocks & Amaha have noticed certain media pages

misrepresenting content associated with this initiative and Janhvi Kapoor. This is deeply concerning."

"We want to be clear, Janhvi Kapoor is part of this conversation as a caregiver and ally, not as someone who has had any personal experience of addiction or alcohol dependence. Such misrepresentation not only diminishes her role, but also undermines and disrespects the real, lived experiences of those battling addiction and those supporting them. Let's not trivialise efforts to lend a healing hand to a critical problem by misleading information for the sake of clickbait," the statement further read.

It concluded with, "We strongly call upon media outlets, digital platforms, and individuals to report with integrity and ensure conversations around addiction are handled with the sensitivity they deserve. Misinformation in this space is harmful, irresponsible, and disrespectful to the very community this dialogue aims to support. Thank you for standing with us."

What did Janhvi say?

Janhvi, on the Raj Shamani Podcast, shared, "I would not say I was addicted or I was abusing alcohol, but I was drinking frequently. And this was after a very traumatic experience in my life. I felt the need to just, like, 'I need to get drunk'."Janhvi also revealed that the realisation did not arrive through a dramatic breaking point. Instead, it came from noticing how

Katrina Kaif And Vicky Kaushal Make FIRST Joint Appearance After Welcoming Son Vihaan

Vicky Kaushal and Katrina Kaif were spotted out and about in Mumbai on Sunday evening, marking one of their first proper public appearances together after welcoming their son. The couple kept it effortlessly stylish in coordinated looks, with Katrina opting for an oversized black coat paired with black pants and chunky sneakers, finishing the look with dark sunglasses. Vicky, meanwhile, kept it casual in a black T-shirt and trousers layered with a brown suede jacket and a cap, completing his look with beige sneakers.

The clips have gone viral as Katrina has largely stayed away from the public eye since becoming a mother, making this one of her first proper appearances post-delivery. The couple welcomed their first child, a baby boy named Vihaan Kaushal, on November 7, 2025, sharing the news with a heartfelt statement.

Katrina and Vicky had earlier announced their pregnancy in September 2025 with a joint post that read, "On our way to start the best chapter of our lives with hearts full of joy and gratitude." The announcement came after months of speculation, and Katrina kept a relatively low profile throughout her pregnancy.

The couple got married on December 9, 2021, in an intimate ceremony at Six Senses Fort Barwara in Rajasthan.On the work front, Katrina was last seen in Merry Christmas (2024), which released on January 12, 2024, marking her most recent on-screen appearance, after which she has not announced a new film and has largely stayed away from the spotlight, especially during her pregnancy and after welcoming her son. Vicky Kaushal, meanwhile, was last seen in the 2025 historical action film Chhaava, which went on to become one of the biggest hits of the year. He is currently working on Love & War, directed by Sanjay Leela Bhansali and co-starring Ranbir Kapoor and Alia Bhatt. The film is one of the most anticipated projects in Bollywood and is currently under production.

Huma Qureshi, Rachit Singh Set To Marry Later This Year, Wedding Prep Begins

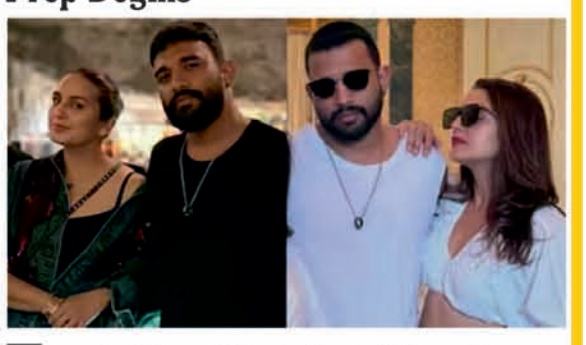

Looks like wedding bells might be on the way for Huma Qureshi and this time, it's not just rumours doing the rounds. Something real seems to be quietly coming together behind the scenes.As per a report by Hindustan Times, Huma and her partner Rachit Singh are planning to get married later this year. The couple, who have mostly kept their relationship private, have already begun preparations for their big day.

A source told Hindustan Times, "They are planning an October end or November wedding as of now. The preparations have begun."The celebrations are expected to reflect Huma's personal style – simple, warm, and close-knit. Sharing more details, the source added, "Knowing Huma she will have a good intimate wedding party and then throw a reception for the industry. May be not a lavish wedding but something that only her close friends and family will attend, followed by a big reception. As of now its most probably looking like Mumbai."

Speculation about their relationship had been growing for a while. The two were spotted together at a screening of Thamma and later attended Sonakshi Sinha's wedding, which caught attention. In September 2025, Hindustan Times had earlier reported that the couple got engaged in the US.Speaking about the proposal, a source had shared, "Huma and Rachit have been going strong for a while as a couple and on Sunday, he proposed to her in an intimate proposal and she said yes. It was a close-knit affair that took place in the US. They are yet to decide when they want to make it official by announcing it publicly."

The two were also recently seen travelling together from the Mumbai airport, one of the rare times they've been spotted publicly as a couple.

Rachit Singh, originally from Varanasi, moved to New Delhi in 2012 and briefly explored modelling before shifting to Mumbai in 2016 to pursue a career in entertainment, according to his IMDb profile.Early in his journey, he worked closely with casting director Atul Mongia and helped set up Artist Collective, a platform focused on actor training. Over the years, he has built a strong reputation as an acting coach.Through his initiative, Rachit Singh Workshop, he has conducted more than 100 sessions, working with several well-known names including Ranveer Singh, Varun Dhawan, Vicky Kaushal, Anushka Sharma, Gulshan Devaiah, Imaad Shah, Kunal Kapoor, Pooja Hegde, Harshvardhan Rane, Amruta Subhash, Shahana Goswami, Ahana Kumra, Aneet Padda, and Shanaya Kapoor.